नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 147
दि. 01.03.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

मतदाता सूची पुनरीक्षण पर गुजरात विधानसभा में तीखा टकराव विपक्ष ने उठाए सवाल, सरकार ने बताया संवैधानिक प्रक्रिया

अहमदाबाद। गुजरात विधानसभा में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मतदाता सूची में किए गए बदलाव को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखा राजनीतिक संघर्ष देखने को मिला। यह विवाद केवल प्रशासनिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अधिकार—मताधिकार—की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर केंद्रित हो गया। विपक्षी दलों ने मतदाता सूची से नाम हटाने में कथित अनियमितताओं और साजिश का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने पूरे अभियान को संवैधानिक और नियमों के अनुरूप बताया।

विधानसभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आरोप लगाया कि राज्य में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए फॉर्म-7 का दुरुपयोग किया गया है। विपक्ष का कहना है कि हजारों नागरिकों के नाम उनकी जानकारी और सहमति के बिना हटाने के लिए आवेदन किए गए। कांग्रेस नेता अमित चावड़ा ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि यदि प्रशासनिक स्तर पर इस तरह की अनियमितताएं हो रही हैं, तो विधानसभा को इस पर जवाबदेही तय करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या जानबूझकर की गई कार्रवाई लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर सकती है।

वहीं, विधायक जिग्नेश मेवाणी ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से नाम हटाने

की प्रक्रिया का सबसे अधिक प्रभाव घुमंतू और हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर पड़ा है। उन्होंने इसे इन समुदायों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताते हुए कहा कि सरकार को इस प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन न हो। जैसे-जैसे बहस तेज हुई, राज्य के मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने संविधान का हवाला देते हुए सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची तैयार करना और उसका पुनरीक्षण करना पूरी तरह से भारत निर्वाचन आयोग का अधिकार क्षेत्र है, जो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विधानसभा को चुनाव आयोग के संवैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, और इस प्रकार की बहस से आयोग की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है।

भारतीय जनता पार्टी के विधायक रमणलाल वोरा ने भी सरकार के पक्ष का समर्थन करते हुए कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक नियमित और आवश्यक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में मृत मतदाताओं, स्थानांतरित हो चुके लोगों और दोहराए गए नामों को हटाना आवश्यक होता है, ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे। हालांकि, विपक्ष ने यह तर्क दिया कि यदि इस अभियान पर राज्य के खजाने से खर्च किया जा रहा है, तो विधानसभा को इसकी समीक्षा करने का पूरा अधिकार है। कांग्रेस विधायक शैलेष परमार ने कहा कि विपक्ष चुनाव आयोग की स्वायत्तता पर सवाल नहीं उठा रहा है, बल्कि उस प्रशासनिक व्यवस्था की जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहता है, जो करदाताओं के धन से इस प्रक्रिया को लागू कर रही है। इस विवाद के बीच विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी ने हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों को संतुलित करने का प्रयास किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकारों पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन प्रशासनिक खर्च और प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों पर सीमित चर्चा की जा सकती है। उन्होंने सभी विधायकों को निर्देश दिया कि वे चर्चा के दौरान चुनाव आयोग की गरिमा और संवैधानिक स्थिति का सम्मान करें। विवाद के दौरान राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि केवल फॉर्म-7 भर देने से किसी भी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाता। उन्होंने बताया कि इसके बाद बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन किया जाता है और संबंधित व्यक्ति को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाता है। पूरी जांच और सुनवाई के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाता है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि सरकार पूरी पारदर्शिता और नियमों के अनुसार कार्य कर रही है।

लंबी बहस और तीखी नोकझोंक के बाद, विपक्ष के विरोध के बावजूद अनुपूरक विनियोग विधेयक 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक के पारित होने के साथ ही मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े प्रशासनिक खर्च को औपचारिक मंजूरी मिल गई। इसी बीच, कोलकाता से भी मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने जानकारी दी कि विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद राज्य की मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 7.04 करोड़ से अधिक हो गई है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान फॉर्म-7 के माध्यम से 5.46 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए, जबकि फॉर्म-6 और फॉर्म 6-ए के जरिए 1.82 लाख से अधिक नए मतदाताओं को सूची में जोड़ा गया।

पश्चिम एशिया युद्ध की चपेट में, अमेरिका-इजरायल के हमले के बाद ईरान का भीषण पलटवार, वैश्विक तनाव चरम पर

तेहरान। पश्चिम एशिया एक बार फिर बड़े सैन्य टकराव का केंद्र बन गया है। इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए व्यापक हवाई हमलों के बाद क्षेत्र में हालात अत्यंत गंभीर हो गए हैं। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल और खाड़ी क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सैकड़ों मिसाइलें दाग दीं, जिससे पूरे क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। इस संघर्ष में अब तक बड़ी संख्या में नागरिक हताहत हुए हैं, जिनमें स्कूली छात्राएं भी शामिल हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता और निंदा बढ़ गई है। ईरानी समाचार एजेंसियों के अनुसार, शनिवार सुबह इजरायल ने अमेरिका के सहयोग से ईरान की राजधानी तेहरान सहित लगभग दस प्रमुख शहरों पर हवाई हमले किए। इन हमलों का मुख्य लक्ष्य ईरान के सैन्य प्रतिष्ठान, मिसाइल केंद्र और रणनीतिक ठिकाने बताए जा रहे हैं। हालांकि, हमलों के दौरान दक्षिणी ईरान के एक विद्यालय पर मिसाइल गिरने से 85 छात्राओं की दर्दनाक मौत हो गई और 45 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गईं। इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है और इसे युद्ध की सबसे दुखद घटनाओं में से एक माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, इन हमलों के प्रमुख निशानों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई भी शामिल थे, हालांकि वे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ईरान ने इस हमले को अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बताते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया है। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि यह कार्रवाई अमेरिकी नागरिकों और

सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उसने अपने सैन्य कार्यक्रम और मिसाइल क्षमताओं को नहीं रोका तो उसे और भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप का बयान "हथियार डालो या मौत चुनो" वैश्विक स्तर पर व्यापक चर्चा का विषय बन गया है।

इजरायल ने इस सैन्य अभियान को "लायंस रोअर" नाम दिया है, जिसका उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना बताया जा रहा है। इजरायली अधिकारियों का दावा है कि यह हमला ईरान के बढ़ते परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को रोकने के लिए आवश्यक था। ईरान ने भी इस हमले का तुरंत जवाब देते हुए इजरायल पर लगभग 400 मिसाइलें दागीं। इसके साथ ही ईरान ने कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। इस जवाबी कार्रवाई ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है।

विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख शहर दुबई में विस्फोटों की आवाज सुनाई देने के बाद प्रशासन ने एहतियातन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को खाली करा दिया। इसके अलावा दुबई सहित कई खाड़ी देशों के एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए और सभी उड़ानें अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गईं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने ईरान, इजरायल और खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों से घरों के अंदर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। भारतीय एयरलाइंस एअर इंडिया और इंडिगो ने भी सुरक्षा कारणों से अपने कई उड़ान संचालन रोक दिए हैं। कुछ उड़ानों को बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा, जबकि कुछ को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया गया। ईरान के विदेश मंत्री ने इस हमले को पूरी तरह गैर-कानूनी और अंतरराष्ट्रीय कानून के विरुद्ध बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी संप्रभुता और नागरिकों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि कूटनीतिक समाधान का अवसर दिया जाए तो ईरान बातचीत के लिए तैयार है। इस बीच, बढ़ते तनाव को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। इस बैठक में क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर चर्चा होगी तथा युद्ध को रोकने के उपायों पर विचार किया जाएगा। रूस, चीन, फ्रांस और अन्य देशों ने इस सैन्य कार्रवाई पर चिंता व्यक्त की है और तत्काल युद्धविराम की मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह संघर्ष केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक प्रभाव वाला हो सकता है। पश्चिम एशिया विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख केंद्र है और यहां किसी भी प्रकार की अस्थिरता का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तेल की कीमतों में पहले ही उछाल देखा जा रहा है और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चितता बढ़ गई है। इस युद्ध ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या सैन्य शक्ति के माध्यम से स्थायी शांति स्थापित की जा सकती है। जहां एक ओर अमेरिका और इजरायल अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि बता रहे हैं, वहीं ईरान इसे अपनी संप्रभुता और अस्तित्व की लड़ाई मान रहा है। इस टकराव ने पूरे विश्व को चिंतित कर दिया है और अब सभी की निगाहें कूटनीतिक प्रयासों और संयुक्त राष्ट्र की पहल पर टिकी हैं। यदि स्थिति जल्द नियंत्रित नहीं हुई तो यह संघर्ष और व्यापक रूप ले सकता है, जिससे न केवल पश्चिम एशिया बल्कि पूरी दुनिया की शांति और स्थिरता खतरे में पड़ सकती है।

आधुनिक दौर में बदलने होंगे सैन्य सेवा नियम, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दी नई सोच अपनाने की नसीहत

नई दिल्ली। देश के सैन्य और अर्धसैनिक बलों की सेवा शर्तों और सेवानिवृत्ति आयु को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण संदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश अब डिजिटल और तकनीकी रूप से उन्नत युग में प्रवेश कर चुका है, इसलिए सरकार को भी ब्रिटिश काल की पुरानी प्रशासनिक सोच और नियमों से बाहर निकलकर आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बदलाव करने चाहिए। अदालत ने यह टिप्पणी भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसमें सेवा अवधि और अनुभव के महत्व पर गंभीर सवाल उठाए गए।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार के रुख पर असंतोष जताते हुए कहा कि आधुनिक सैन्य बलों की कार्यप्रणाली, जिम्मेदारियां और तकनीकी आवश्यकताएं पहले की तुलना में काफी बदल चुकी हैं। ऐसे में पुरानी सोच के आधार पर बनाए गए नियम आज के समय की जरूरतों के अनुरूप नहीं माने जा सकते। अदालत ने कहा कि भारतीय तटरक्षक बल जैसे उच्च तकनीकी और विशेषज्ञता वाले संगठन में अधिकारियों के अनुभव और कौशल का अत्यंत महत्व होता है, और केवल आयु के आधार पर उन्हें सेवा से बाहर करना उचित नहीं हो सकता।

यह पूरा विवाद भारतीय तटरक्षक बल के सेवा नियम 20(1) और 20(2) से जुड़ा हुआ है, जिनके अनुसार कमांडेंट और उससे नीचे के रैंक के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 57 वर्ष निर्धारित की गई थी, जबकि उससे ऊपर के अधिकारियों को 60 वर्ष तक सेवा में बने रहने की अनुमति थी। इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था को चुनौती देते हुए मामला पहले दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा, जहां अदालत ने इस अंतर को समाप्त करते हुए सभी अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष निर्धारित करने का आदेश दिया था। हालांकि, इस निर्णय के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार को इस मुद्दे पर व्यापक समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने अवलोकन में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि अनुभव की कोई निश्चित समाप्ति तिथि नहीं होती। अदालत का मानना है कि विशेष रूप से तकनीकी और रणनीतिक क्षेत्रों में अनुभवी अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे अधिकारियों ने वर्षों तक प्रशिक्षण और सेवा के माध्यम से जो विशेषज्ञता प्राप्त की होती है, वह किसी भी संगठन की कार्यक्षमता और सुरक्षा के लिए अमूल्य होती है। इसलिए केवल आयु सीमा के आधार पर उन्हें सेवा से हटाना संगठन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।

अदालत ने केंद्र सरकार को यह भी सुझाव दिया कि सेवा नियमों को लेकर अत्यधिक कठोर या रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाने के बजाय लचीला और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि आधुनिक युग में सैन्य और सुरक्षा बलों की भूमिका पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल और तकनीकी हो गई है, जिसमें साइबर सुरक्षा, समुद्री निगरानी, उन्नत उपकरणों का संचालन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे कई नए आयाम जुड़ गए हैं। ऐसे में अनुभवी अधिकारियों की सेवाएं और मार्गदर्शन संगठन के लिए अत्यंत उपयोगी हो सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केवल टिप्पणी ही नहीं की, बल्कि ठोस कदम उठाते हुए केंद्र सरकार को एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का आदेश भी दिया है। यह समिति भारतीय तटरक्षक बल और अन्य सशस्त्र बलों की सेवा शर्तों, सेवानिवृत्ति आयु और कार्यप्रणाली की व्यापक समीक्षा करेगी। समिति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि सेवा नियम आधुनिक आवश्यकताओं, तकनीकी प्रगति और संगठन की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप हों। समिति अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आवश्यक है कि भारतीय तटरक्षक बल की तुलना अन्य अर्धसैनिक बलों जैसे सीआरपीएफ और बीएसएफ से करते समय उनके कार्यक्षेत्र, जिम्मेदारियों और परिचालन परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए। तटरक्षक बल समुद्र में अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करता है, जहां तकनीकी दक्षता, मानसिक सतर्कता और शारीरिक क्षमता तीनों का संतुलन आवश्यक होता है।

केंद्र सरकार की ओर से अदालत में यह तर्क दिया गया कि भारतीय तटरक्षक बल का कार्य अत्यंत कठिन और जोखिमपूर्ण होता है, जिसमें अधिकारियों को समुद्र में लंबे समय तक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है। सरकार का कहना है कि ऐसे कार्यों के लिए युवा, ऊर्जावान और शारीरिक रूप से पूरी तरह सक्षम अधिकारियों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा कि तटरक्षक बल सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसकी संरचना तथा कार्यप्रणाली अन्य अर्धसैनिक बलों से अलग है, इसलिए इसकी तुलना अन्य बलों से करना पूरी तरह उचित नहीं होगा।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को पूरी तरह खारिज नहीं किया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि सेवा नियमों का निर्धारण करते समय केवल शारीरिक क्षमता ही नहीं, बल्कि अनुभव, विशेषज्ञता और संगठनात्मक आवश्यकता जैसे अन्य महत्वपूर्ण कारकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि आधुनिक सैन्य संगठनों में तकनीकी और रणनीतिक दक्षता का महत्व लगातार बढ़ रहा है, और अनुभवी अधिकारियों की भूमिका इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

बांग्लादेश तनाव का असर, भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या में गिरावट, भारतीयों की विदेश यात्रा में बढ़ोतरी

नई दिल्ली। वर्ष 2025 में भारत के पर्यटन क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण झटका लगा है, क्योंकि देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में 9.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में जहां लगभग 99.6 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए थे, वहीं वर्ष 2025 में यह संख्या घटकर 90.2 लाख रह गई। यह गिरावट पर्यटन उद्योग के लिए चिंता का विषय मानी जा रही है, क्योंकि पर्यटन भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और इससे लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है।

इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ बढ़ता राजनयिक तनाव और वीजा प्रतिबंध बताया जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में बांग्लादेश से 17.5 लाख पर्यटक भारत आए थे, जो वर्ष 2025 में घटकर मात्र 4.66 लाख रह गए। यह लगभग 73 प्रतिशत की भारी गिरावट है। भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक और सुरक्षा कारणों से वीजा जारी करने की प्रक्रिया में आई सख्ती ने इस कमी में प्रमुख भूमिका निभाई है। चूंकि बांग्लादेश भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के सबसे बड़े स्रोत देशों में से एक रहा है, इसलिए इस कमी का सीधा असर कुल विदेशी पर्यटक संख्या पर पड़ा है।

हालांकि, यदि बांग्लादेश से आने वाले पर्यटकों के आंकड़ों को अलग कर दिया जाए, तो बाकी दुनिया से भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2025 में अन्य देशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में 4.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विशेष रूप से अमेरिका और ब्रिटेन से आने वाले पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है। अमेरिका से 18.1 लाख और ब्रिटेन से 10.7 लाख

पर्यटक भारत पहुंचे, जो दर्शाता है कि भारत अभी भी पश्चिमी देशों के पर्यटकों के लिए एक आकर्षक पर्यटन स्थल बना हुआ है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थल, आध्यात्मिक केंद्र, प्राकृतिक सौंदर्य और विविधता विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, आगरा, जयपुर, केरल और गोवा जैसे पर्यटन स्थल अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। हालांकि, पड़ोसी देशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी ने कुल आंकड़ों को प्रभावित किया है।

दूसरी ओर, भारतीयों में विदेश यात्रा का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2025 में कुल 327.1 लाख भारतीय नागरिकों ने विदेश यात्रा की, जो वर्ष 2024 की तुलना में 5.9 प्रतिशत अधिक है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि भारतीयों की आय में वृद्धि, बेहतर आर्थिक स्थिति और वैश्विक संपर्क बढ़ने से विदेश यात्रा अब पहले की तुलना में अधिक सुलभ हो गई है।

भारतीय यात्रियों के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य संयुक्त अरब अमीरात रहा, जहां कुल यात्रियों के 26.3 प्रतिशत लोग पहुंचे। इसके अलावा सऊदी अरब, थाईलैंड, सिंगापुर और अमेरिका भी भारतीयों के प्रमुख यात्रा गंतव्यों में शामिल रहे। इन देशों में बेहतर पर्यटन सुविधाएं, आधुनिक बुनियादी ढांचा और भारतीय पर्यटकों के लिए अनुकूल वातावरण प्रमुख आकर्षण के रूप में सामने आए हैं। आंकड़ों के अनुसार, विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों में से 43.5 प्रतिशत लोगों का मुख्य उद्देश्य छुट्टियां मनाना था। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने, शिक्षा प्राप्त करने और व्यापारिक उद्देश्यों के लिए भी विदेश गए। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि भारतीय समाज में वैश्विक संपर्क और अंतरराष्ट्रीय यात्रा की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है।

भारत से विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए दिल्ली सबसे बड़ा प्रस्थान केंद्र रहा, जबकि मुंबई दूसरे स्थान पर रहा। इन दोनों शहरों के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल हैं और यहां से बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती हैं।

पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी पर्यटकों की संख्या में आई यह गिरावट अस्थायी हो सकती है। यदि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में सुधार होता है और वीजा प्रक्रिया में ढील दी जाती है, तो आने वाले वर्षों में विदेशी पर्यटकों की संख्या में फिर से वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयास, जैसे डिजिटल वीजा सुविधा, पर्यटन बुनियादी ढांचे का विकास और वैश्विक स्तर पर प्रचार अभियान, भविष्य में सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं।

भारत का पर्यटन उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह न केवल विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। होटल, परिवहन, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यापार और सेवा क्षेत्र सीधे तौर पर पर्यटन पर निर्भर हैं। ऐसे में विदेशी पर्यटकों की संख्या में गिरावट इन क्षेत्रों के लिए चुनौती बन सकती है।

वर्तमान स्थिति यह भी दर्शाती है कि भारत का पर्यटन बाजार एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जहां एक ओर विदेशी पर्यटकों की संख्या में अस्थायी कमी आई है, वहीं दूसरी ओर भारतीय नागरिकों की विदेश यात्रा में वृद्धि हो रही है। यह प्रवृत्ति भारत की बदलती आर्थिक और सामाजिक स्थिति को भी प्रतिबिंबित करती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत अपनी पर्यटन नीतियों को और मजबूत करे, सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने पर्यटन स्थलों का प्रभावी प्रचार करे, तो आने वाले वर्षों में भारत फिर से विदेशी पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण केंद्र बन सकता है। भारत की सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक विरासत और आध्यात्मिक परंपरा उसे विश्व पर्यटन मानचित्र पर एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

शिक्षा में न्यायपालिका : संवाद की जरूरत या विवाद की राजनीति?

एक बार फिर शिक्षा से जुड़ा एक प्रश्न राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में है। शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा प्रकाशित आठवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में "हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका" शीर्षक अध्याय में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और लंबित मुकदमों का उल्लेख किए जाने पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने नाराजगी प्रकट की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की यह टिप्पणी कि "किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने नहीं दिया जाएगा" केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि संस्थागत गरिमा की रक्षा का संकेत है। इसके बाद संबंधित अध्याय को हटाने और बाजार में उपलब्ध पुस्तकों को वापस लेने का निर्णय लिया गया। प्रश्न यह है कि क्या यह केवल एक संपादकीय चूक थी या हमारे शैक्षिक ढांचे में कहीं गहरी संरचनात्मक कमी है? प्रश्न है कि स्कूली बच्चों को 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' के बारे में जानकारी देने से किस हित की पूर्ति होने वाली है? लेकिन इसमें दो मत नहीं है कि न्यायिक तंत्र के साथ हर क्षेत्र में फैली भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के ठोस उपाय होने ही चाहिए। सबसे पहले यह भी स्वीकार करना होगा कि न्यायपालिका में लंबित मामलों और भ्रष्टाचार जैसे प्रश्न पूरी तरह काल्पनिक नहीं हैं। न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या करोड़ों में है, यह एक सार्वजनिक तथ्य है। कुछ मामलों में न्यायिक आचरण पर भी प्रश्न उठे हैं। परंतु उतना ही सत्य यह भी है कि भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर अपनी स्वतंत्रता, पारदर्शिता और सक्रियता से लोकतंत्र की रक्षा की है। पिछले वर्षों में शीर्ष न्यायाधीशों द्वारा अपनी संपत्तियों का सार्वजनिक विवरण देने की सहमति जैसे कदमों ने संस्थागत पारदर्शिता को सुदृढ़ किया है। ऐसे में प्रश्न यह नहीं है कि समस्या है या नहीं, प्रश्न यह है कि उसे किस भाषा, किस संतुलन और किस शैक्षिक दृष्टि से प्रस्तुत किया जाए। शिक्षा का उद्देश्य केवल तथ्य देना नहीं, दृष्टि देना है। यदि हम बच्चों को यह सिखाते हैं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, तो साथ ही यह भी सिखाना होगा कि न्यायपालिका ने भ्रष्टाचार से लड़ने में कैसी भूमिका निभाई है, उसने प्रशासनिक दुरुपयोग पर कैसे अंकुश लगाया है, नागरिक अधिकारों की रक्षा में कैसे ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं। शिक्षा में आलोचना हो, पर निराशा नहीं, तथ्य हों, पर संतुलन भी हो। यदि किसी अध्याय में केवल संस्थागत विकृतियों का उल्लेख हो और सुधारात्मक प्रयासों, आदर्श उदाहरणों और संवैधानिक मूल्यों का समुचित विवेचन न हो, तो वह शिक्षा में मूल्यों एवं आदर्शों के बजाय अविश्वास का बीजारोपण बन सकता है। यह विवाद एक बड़े प्रश्न को भी जन्म देता है-पाठ्य पुस्तकों की निर्माण प्रक्रिया में बहुस्तरीय समीक्षा के बावजूद ऐसी सामग्री कैसे प्रकाशित हो जाती है? क्या संपादकीय बोर्ड में विविध दृष्टिकोणों का अभाव है? क्या विधि विशेषज्ञों, शिक्षाशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों के बीच समन्वय पर्याप्त नहीं है? एक लोकतांत्रिक समाज में संस्थाओं की आलोचना वर्जित नहीं हो सकती, पर आलोचना और अवमूल्यन के बीच महीन रेखा होती है। शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी जैसी संस्थाओं का दायित्व है कि वे इस रेखा को पहचानें। यह भी स्मरणीय है कि भ्रष्टाचार केवल न्यायपालिका तक सीमित समस्या नहीं है। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इसी महीने जारी रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 182 देशों के बीच भारत की रैंक 91 है। पिछले साल के मुकाबले भारत ने 5 स्थान का सुधार किया है, यह स्थिति सुधार के बावजूद मध्य स्तर पर बनी हुई बताई गई है। इसका अर्थ है कि भ्रष्टाचार एक संरचनात्मक, सामाजिक और प्रशासनिक चुनौती है। यदि हम बच्चों को इसके बारे में पढ़ाते हैं तो उसे एक समग्र सामाजिक संदर्भ में पढ़ाया जाना चाहिए कि यह समस्या क्यों उत्पन्न होती है, इसे रोकने के लिए क्या संवैधानिक तंत्र हैं, नागरिकों की क्या भूमिका है और सुधार की संभावनाएं क्या हैं। केवल किसी एक संस्था को केंद्र में रखकर समस्या का चित्रण करना न तो शैक्षिक रूप से न्यायोचित है और न ही संवैधानिक संतुलन के अनुरूप। न्यायपालिका की गरिमा का प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र तीन स्तंभों-विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर आधारित है।

वोट के लिए मुफ्त की रेवड़ी से कर्जे के अंधकूप में देश

> इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मुफ्त की चीजें देकर राज्य सरकारें लोगों की आदतें खराब कर रही है। कोर्ट ने आगे कहा कि इन लोगों का रोजगार सृजन पर ध्यान देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कई राज्य सरकारें कर्ज और घाटे से दबी हुई हैं। इसके बावजूद वे मुफ्त योजनाएं बांट रही हैं।

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ त्से-तुंग ने कहा था कि किसी आदमी को एक मछली दो और तुम उसे एक दिन के लिए खिलाओगे। उसे मछली पकड़ना सिखाओ और तुम उसे ज़िंदगी भर खिलाओगे। आज के भारतीय शब्दों में यह है कि हर नेता जो मुफ्त चीजों का वादा करता है, असल में यह कह रहा है कि मैं तुम्हें एक अच्छी रोजी-रोटी और रेगुलर इनकम की इज्जत नहीं दे सकता। इसलिए अभी के लिए यह कुछ है, इसी से काम चला लो। चुनाव आते ही मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए राजनैतिक दलों में मुफ़्त की रेवड़ी बाँटने की होड़ लग जाती है। कोई मुफ़्त बिजली और पानी देने की बात करता है तो कोई स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप, साइकिल और टीवी की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त सुविधाएं देने की संस्कृति की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि देश के आर्थिक विकास में बाधा डालने वाली ऐसी नीतियों पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है। तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक याचिका दायर कर उपभोक्ताओं की वित्तीय स्थिति पर गौर किए बिना हर किसी को निःशुल्क बिजली प्रदान करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, कोर्ट ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) सरकार के नेतृत्व वाली बिजली वितरण कंपनी की मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखने वाली याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया है। बिजली वितरण कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में विद्युत संशोधन नियम, 2024 के एक नियम को चुनौती दी थी।

इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मुफ्त की चीजें देकर राज्य सरकारें लोगों की आदतें खराब कर रही है। कोर्ट ने आगे

कहा कि इन लोगों का रोजगार सृजन पर ध्यान देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कई राज्य सरकारें कर्ज और घाटे से दबी हुई हैं। इसके बावजूद वे मुफ्त योजनाएं बांट रही हैं। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने पूछा कि बिजली शुल्क अधिसूचित होने के बाद तमिलनाडु की कंपनी ने अचानक जेब ढीली करने का फैसला क्यों किया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा राज्यों को रोजगार के रास्ते खोलने के लिए काम करना चाहिए। अगर आप सुबह से शाम तक मुफ्त भोजन देना शुरू कर देंगे, फिर मुफ्त साइकिल, मुफ्त बिजली देंगे, तो कौन काम करेगा और फिर कार्य संस्कृति का क्या होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि वैलफेयर के तौर पर आप उन लोगों को देना चाहते हैं जो बिजली का चार्ज नहीं दे सकते, लेकिन जो लोग खर्च उठा सकते हैं और जो नहीं उठा सकते, उनके बीच फर्क किए बिना, आप बांटना शुरू कर देते हैं। तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेन्नारसु ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अंतरिम बजट पेश किया था। इसमें अनुमान के मुताबिक, राज्य का कुल बकाया कर्ज बढ़कर 10.71 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। इस बढ़ते कर्ज के लिए वित्त मंत्री थंगम थेन्नारसु ने केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र तमिलनाडु में वित्तीय अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की मंजूरी नहीं दे रही है और केंद्र प्रायोजित योजनाओं का फंड रोक रही है। उन्होंने जीएसटी दरों में कटौती और 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पर भी निराशा जताई।

मंत्री थेन्नारसु के अनुसार संघीय ढांचे में राज्यों के साथ ऐसा अनुचित व्यवहार पहले कभी नहीं देखा गया। द्रमुक (डीएमके) सरकार ने अपनी फ्लैगशिप योजनाओं के लिए फंड की कमी नहीं होने दी। महिलाओं के लिए 'विदियाल पयानम' योजना (मुफ्त बस यात्रा) के लिए 4,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इसके अलावा, छात्रों के लिए बस किराए की योजना हेतु 1,782 करोड़ रुपये और डीजल सब्सिडी के लिए 1,857 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर परिवहन विभाग को 13,062 करोड़ रुपये मिले। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए भी सरकार ने 5,463 करोड़ रुपये का बड़ा हिस्सा अलग रखा है। तमिलनाडु में पिछले 4 वर्षों में प्रति परिवार कर्ज तेजी से बढ़कर लगभग 3.7 लाख रुपए तक पहुंच गया है, जो राज्य की गंभीर वित्तीय स्थिति को दर्शाता है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु पर देश में सर्वाधिक 8.34 लाख करोड़ रुपये कर्ज है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। इस पर 7.69 लाख करोड़ रुपये कर्जा है। इसी तरह महाराष्ट्र पर 7.22 लाख करोड़, पश्चिम बंगाल पर 6.58 लाख करोड़ रुपये, कर्नाटक पर 5.97 लाख करोड़ रुपये, राजस्थान पर 5.62 लाख करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश पर 4.85 करोड़ रुपये का कर्जा है। गुजरात पर 4.67 लाख करोड़ रुपये, केरल पर 4.29 लाख करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश पर 4.18 लाख करोड़ रुपये, तेलंगाना पर 3.89 लाख करोड़ रुपये, पंजाब पर 3.51 लाख करोड़ रुपये, हरियाणा पर 3.36 लाख करोड़ रुपये, बिहार पर 3.19 लाख करोड़ रुपये और असम पर 1.51 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। वर्ष 2016-17 के बाद कर्ज पर निर्भरता लगातार बढ़ती गई।

वोट बैंक की राजनीतिक के कारण ऐसी लोकलुभावन मुफ्त की योजनाओं के कारण छोटा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश डेब्ट ट्रैप में फंस गया है। आलम यह है कि हिमाचल सरकार के पास लिए गए कर्ज की मूल रकम व उस पर लगने वाले ब्याज को चुकाने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं है। वहीं, कर्ज लेने की लिमिट सिर्फ 10 हजार करोड़ रुपए है। अगले वित्तीय वर्ष में कर्ज व ब्याज चुकाने के लिए 13 हजार करोड़ चाहिए। अब लोन को चुकाने के लिए मार्केट से कर्ज लेकर भी बात नहीं बन रही और तीन हजार करोड़ रुपए अपने बजट से चुकाने होंगे। सोलहवें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में हिमाचल सहित अन्य कुछ राज्यों की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (आरडीजी) खत्म कर दी है। इससे हिमाचल सरकार के खजाने पर भारी चोट लगी है। हिमाचल प्रदेश पर कुल देनदारियां 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई हैं, जिससे यह पहाड़ी राज्य कर्ज लेने वाले भारतीय राज्यों में 5वें स्थान पर पहुंच गया है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 'स्टेट फाइनेंस' रिपोर्ट (2025-26) में कहा है कि मुफ्त की ऐसी योजनाओं के चलते राज्यों के बजट पर दबाव बढ़ रहा है। हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में बुनियादी ढांचे (सड़क, स्कूल, अस्पताल) पर खर्च कुल बजट का 10% से भी कम रह गया है। मुफ्त की रेवड़ी बांटने में कोई पीछे नहीं है। केंद्र में बतौर विपक्षी पार्टी आलोचना करने वाली कांग्रेस अपनी सत्ता वाले राज्यों में खुल कर 'रेवड़ियां' बांटती रही है। उसी तरह केंद्र में खुल कर यह काम करने वाली भाजपा, राज्यों में कांग्रेस व अन्य पार्टियों का इसके लिए विरोध करती है। बीते नौ साल में प्रति व्यक्ति कर्ज तीन गुना बढ़ गया है। इसका एक बड़ा कारण केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा जनता को खुले आम 'रेवड़ियां' बांटना भी है। देश में प्रति व्यक्ति कर्ज 1,86,206 रुपए हो जाने का अनुमान है। अहम बात यह है कि राजनीतिक दलों को यह भी बताना चाहिए कि इन मुफ्त की योजनाओं के लिए धन कहां से आएगा। अब हमारी फाइनेंशियल पॉलिटिक्स में ईमानदारी और जवाबदेही वापस लाने का समय आ गया है।

प्रेरणा

सत्य का हृदय और मानव धर्म का रहस्य

प्राचीन काल में बनारस की पवित्र भूमि पर सज्जन नाम के एक महान ज्ञानी गुरु निवास करते थे। उनका आश्रम गंगा के तट से अधिक दूर नहीं था, जहाँ प्रातःकाल की पहली किरण जब जल पर पड़ती थी तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे स्वयं प्रकृति भी उनके ज्ञान को प्रणाम कर रही हो। उनके आश्रम में दूर-दूर से शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आते थे। वे केवल शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं देते थे, बल्कि जीवन का गूढ़ रहस्य भी समझाते थे। उनके अनुसार जीवन केवल सांसों का प्रवाह नहीं, बल्कि सत्य, करुणा और धर्म के संतुलन का नाम है।

एक दिन प्रातःकाल का समय था। हल्की हवा बह रही थी और आश्रम के प्रांगण में खड़े विशाल आम के वृक्ष के नीचे गुरु सज्जन अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उनके शब्दों में ऐसी गहराई थी कि शिष्य मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। गुरु ने कहा, "मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण उसका सत्य है। सत्य वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। यदि मनुष्य सत्य का साथ छोड़ देता है, तो वह स्वयं अपने अस्तित्व से दूर हो जाता है।" शिष्य ध्यानपूर्वक यह उपदेश सुन ही रहे थे कि अचानक एक व्यक्ति दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा। उसकी साँसें तेज चल रही थीं, शरीर पसीने से भीगा हुआ था और आँखों में भय स्पष्ट झलक रहा था। वह सीधे गुरु के चरणों में गिर पड़ा और काँपती आवाज में बोला, "गुरुजी! मेरी रक्षा कीजिए। मेरे प्राण संकट में हैं। यदि मैं मर गया तो मेरे अंधे माता-पिता का सहारा कोई नहीं रहेगा।"

गुरु ने उसे शांत करते हुए पूछा, "वत्स, ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें अपने प्राणों का भय है?"

वह बोला, "मैं एक शिकारी हूँ। आज जंगल में मैंने शिकार समझकर तीर चलाया, परंतु वह एक आदिवासी को लग गया। अब उनके साथी मुझे मारने के लिए पीछे-पीछे आ रहे हैं। मैं अपनी जान बचाकर यहाँ तक भाग आया हूँ। कृपया मेरी रक्षा कीजिए।"

गुरु ने उसकी आँखों में देखा। वहाँ केवल भय ही नहीं, बल्कि पश्चाताप भी था। गुरु ने शांत स्वर में कहा, "जो व्यक्ति शरण में आता है, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। तुम आश्रम के अंदर जाकर एक कोने में छिप जाओ और निश्चिंत रहो।"

वह व्यक्ति तुरंत आश्रम के अंदर चला गया और एक अंधेरे कोने में छिप गया। कुछ ही क्षण बीते थे कि आदिवासियों का एक समूह वहाँ आ पहुँचा। उनके हाथों में तीर और भाले थे, और उनके चेहरे क्रोध से लाल थे। उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और पूछा, "महात्मा जी, क्या आपने किसी व्यक्ति को इधर से भागते हुए देखा है? उसने हमारे साथी को घायल कर दिया है।" यह एक अत्यंत कठिन क्षण था। एक ओर सत्य का सिद्धांत था, जिसे गुरु अभी-अभी अपने शिष्यों को सिखा रहे थे, और दूसरी ओर एक व्यक्ति का जीवन था, जिसने उनकी शरण ली थी। शिष्यों की दृष्टि भी गुरु पर टिक गई। वे जानना चाहते थे कि गुरु अब क्या करेंगे।

गुरु ने शांत और स्थिर स्वर में उत्तर दिया, "इधर से कोई व्यक्ति नहीं गुजरा।"

उनके शब्दों में इतनी गंभीरता और सच्चाई का भाव था कि आदिवासियों को कोई संदेह नहीं हुआ। वे तुरंत दूसरे मार्ग की ओर चले गए।

आश्रम में पुनः शांति छा गई, लेकिन शिष्यों के मन में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ। एक शिष्य ने साहस करके पूछा, "गुरुजी, अभी कुछ समय पहले आप हमें सत्य बोलने का उपदेश दे रहे थे, लेकिन आपने अभी असत्य क्यों कहा? क्या यह आपके उपदेश के विपरीत नहीं है?"

गुरु सज्जन ने मुस्कराते हुए शिष्य की ओर देखा। उनकी आँखों में करुणा और गहराई थी। उन्होंने कहा, "वत्स, सत्य केवल शब्दों में नहीं होता, सत्य का निवास हृदय में होता है। यदि शब्द सत्य हों, लेकिन उनसे किसी निर्दोष का जीवन नष्ट हो जाए, तो वह सत्य नहीं, कठोरता है। और यदि शब्द असत्य हों, लेकिन उनसे किसी प्राणी का जीवन बच जाए, तो वह असत्य नहीं, धर्म है।"

शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। गुरु ने आगे कहा, "मानव धर्म केवल नियमों का पालन करना नहीं है। मानव धर्म करुणा है, दया है, और जीवन की रक्षा है। यदि सत्य किसी की मृत्यु का कारण बन जाए और असत्य किसी के जीवन का कारण बन जाए, तो उस क्षण असत्य ही सच्चा धर्म बन जाता है।" उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, "कल्पना करो, यदि कोई निर्दोष व्यक्ति किसी हत्यारे से बचने के लिए तुम्हारी शरण में आए, और हत्यारा तुमसे पूछे कि वह कहाँ है, तो क्या तुम उसे सच बताकर उसकी हत्या होने दोगे? यदि तुम ऐसा करते हो, तो तुमने सत्य तो बोला, लेकिन धर्म का पालन नहीं किया।" शिष्यों के मन में अब स्पष्टता आने लगी थी। उन्हें समझ में आ रहा था कि सत्य केवल बाहरी नियम नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना का विषय है।

गुरु ने आगे कहा, "सत्य का अर्थ केवल तथ्य बताना नहीं है। सत्य का अर्थ है, वह करना जिससे जीवन की रक्षा हो, जिससे करुणा बनी रहे, जिससे मानवता सुरक्षित रहे। यदि सत्य और करुणा में कभी संघर्ष हो, तो करुणा को चुनना ही सच्चा धर्म है, क्योंकि करुणा ही सत्य का हृदय है।"

तभी वह शिकारी धीरे-धीरे बाहर आया। उसकी आँखों में कृतज्ञता के आँसू थे। उसने गुरु के चरणों में गिरकर कहा, "गुरुदेव, आपने मेरे प्राण बचाए। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूँगा।"

गुरु ने उसे उठाते हुए कहा, "वत्स, मैंने केवल अपना धर्म निभाया है। अब तुम भी अपना धर्म निभाओ। जीवन में कभी किसी निर्दोष प्राणी को हानि मत पहुँचाना। आज तुम्हें अपने कर्म का परिणाम समझ में आ गया है। इस अनुभव को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ।" उस व्यक्ति ने प्रण किया कि वह अब कभी हिंसा नहीं करेगा।

उस दिन शिष्यों ने केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य सीखा। उन्होंने समझा कि धर्म केवल नियमों का पालन नहीं है, बल्कि परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय लेना है। सत्य वह नहीं जो केवल कहा जाए, बल्कि सत्य वह है जो मानवता की रक्षा करे।

समय बीतता गया, लेकिन उस दिन की घटना शिष्यों के हृदय में सदा के लिए अंकित हो गई। उन्होंने समझ लिया कि मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म करुणा है, और सत्य का वास्तविक स्वरूप वही है जो जीवन को बचाए, न कि उसे नष्ट करे।

इस प्रकार गुरु सज्जन ने अपने आचरण से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्म में प्रकट होता है। और यही मानव धर्म का सबसे महान सत्य है।

योगी आदित्यनाथ की विदेश यात्रा से विकास और हिंदुत्व मॉडल हुआ मजबूत!

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री और फायरब्रांड हिन्दू नेता योगी आदित्यनाथ की हालिया सिंगापुर-जापान यात्रा प्रदेश की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को मजबूत करने का एक सशक्त प्रयास है। भले ही सीएम का यह दौरा निवेश आकर्षण और औद्योगिक साझेदारी पर केंद्रित रहा। लेकिन इन दौरों से इस बात के स्पष्ट संकेत मिले कि विकास और हिंदुत्व के मॉडल पर गतिशील यूपी सरकार के लिए निकट भविष्य में 1 ट्रिलियन डॉलर की सूबाई इकॉनमी वाले लक्ष्य को पाना बिल्कुल कठिन नहीं है। आर्थिक विश्लेषक बता रहे हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सहयोगी उपमुख्यमंत्री और भरोसेमंद मंत्रियों के साथ 22 से 26 फरवरी 2026 तक चार दिवसीय विदेश यात्रा पर रहे, उसका अपना महत्व है। सर्वप्रथम उन्होंने 23-24 फरवरी को सिंगापुर की यात्रा की और फिर 25-26 फरवरी को जापान की यात्रा किए।इन दोनों यात्राओं से उन्हें अभूतपूर्व अनुभव हासिल हुआ, जिसके कुछ पलों को उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा भी किया था। कहना न होगा कि 2017 में यूपी की कमान थामने के बाद उनका यह पहला आधिकारिक विदेश दौरा था, जहां उन्होंने निवेशकों, उद्योग प्रतिनिधियों और प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की।

इसलिए योगी की इस विदेश यात्रा के अपने सूबाई मायने हैं, जिसे समझने की जरूरत है। पहला, यह यात्रा यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को गति देगी, विशेषकर अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स, डेटा सेंटर और कौशल विकास में निवेश पर फोकस के साथ। दूसरा, सिंगापुर-जापान जैसे औद्योगिक केंद्रों से साझेदारी प्रदेश को 'मेक इन यूपी' हब बनाने में मदद करेगी, जो राज्य की वैश्विक ब्रांडिंग को मजबूत करेगी। तीसरा, योगी आदित्यनाथ की सिंगापुर-जापान यात्रा से उत्तर प्रदेश को कुल 2.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1.5 लाख करोड़ रुपये के एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, सिंगापुर से लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें 60 हजार करोड़ के एमओयू शामिल हैं। वहीं, जापान से अतिरिक्त निवेश प्रतिबद्धताएं आईं हैं, जो कुल को 2.5 लाख करोड़ तक ले गईं। इन निवेश प्रस्तावों में सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, ऑटोमोटिव, कृषि मशीनरी, लॉजिस्टिक्स, ग्रीन हाइड्रोजन और एविएशन (एमआरओ) जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है। वो भी नामचीन कंपनियों, जैसे- कुबोटा, स्पार्क मिंडा, सुजुकी, होंडा और मित्सुई यदि से, जिनकी अपनी वैश्विक कारोबारी साख है।

जानकारों के मुताबिक, यदि सरकार इन प्रस्तावों को तय समयसीमा में धरातल पर उतारने का लक्ष्य रखती है, और अपने मकसद में कामयाब होती है तो उत्तरप्रदेश में लाखों रोजगार सृजित होंगे और सूबे के 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को महत्वपूर्ण गति मिलेगी। खास बात यह कि योगी आदित्यनाथ की सिंगापुर-जापान यात्रा ने भाजपा को विकास और हिंदुत्व के मॉडल को मजबूत करने का मौका दिया है। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि मुख्यमंत्री का यह दौरा 2027 विधानसभा चुनावों में योगी सरकार की छवि को चमकाने का साधन बनेगा। तभी तो उनका यह दौरा आगामी चुनावों से पहले योगी सरकार की विकास-केंद्रित छवि को रेखांकित करता है। वहीं विपक्ष के सवालों के बावजूद निवेश कूटनीति को बढ़ावा देता है। इससे यूपी की अर्थव्यवस्था को ग्लोबल पटल पर मजबूती मिलेगी। यात्रा से प्राप्त 2.5 लाख करोड़ निवेश प्रस्तावों को भाजपा 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य से जोड़कर प्रचारित करेगी, जो युवाओं में रोजगार सृजन का वादा मजबूत करेगा।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद ने योगी की वैश्विक अपील बढ़ाई, जो 2027 चुनावों में वोटबैंक को एकजुट करने में सहायक होगा। सच कहा जाए तो योगी का यह दौरा यूपी को ग्लोबल इकोनॉमी में स्थापित करेगा, जो केंद्र में भाजपा की नीतियों को समर्थन देगा। वहीं, हिंदुत्व एंगल (जैसे जापान मंदिर दर्शन) ने सांस्कृतिक डिप्लोमेसी को जोड़ा है, जो पार्टी की वैचारिक मजबूती बढ़ाएगा।

यह बात दीगर है कि सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी की इस अभूतपूर्व यात्रा पर तंज कसा, और इसे 'भारत छोड़कर भागना' बताकर विपक्षी हमला बोला। यह उनकी बचकाना सियासी हरकत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वास्तव में, निवेश सफलता ने विपक्ष के आरोपों को कमजोर किया, और भाजपा को योगी आदित्यनाथ को प्रदेश में 'विकास पुरुष' के रूप में पेश करने का आधार दिया, जिसका अपना राजनीतिक महत्व है।

अभियान

रेगिस्तान में विराजित आस्था का जीवंत चमत्कार: सालासर बालाजी धाम की अमर गाथा

राजस्थान की पावन और तपोभूमि सदियों से संतों, सिद्धों और भक्तों की कर्मभूमि रही है। इसी पवित्र धरती पर स्थित सालासर बालाजी मंदिर आज करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। चुरू जिले की सुजानगढ़ तहसील में स्थित यह धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और चमत्कार का ऐसा संगम है, जहाँ हर दिन हजारों भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ विराजमान बालाजी महाराज का स्वरूप संपूर्ण भारत में अद्वितीय माना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान का रूप दाढ़ी और मूंछ वाला है। यह स्वरूप भक्तों को यह अनुभूति कराता है कि प्रभु केवल दिव्य शक्ति ही नहीं, बल्कि एक जीवंत संरक्षक भी हैं, जो हर भक्त के जीवन के संघर्षों में उसके साथ खड़े रहते हैं।

इस पवित्र धाम की स्थापना का इतिहास महान संत महात्मा मोहनदास जी की तपस्या, भक्ति और समर्पण से जुड़ा हुआ है। उनका जन्म एक साधारण लेकिन धार्मिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनका मन सांसारिक विषयों में नहीं लगता था। जहाँ अन्य बच्चे खेलते और जीवन के सामान्य सुखों में आनंद लेते थे, वहीं मोहनदास जी का मन भगवान की भक्ति में लीन रहता था। वे घंटों ध्यान करते, भजन गाते और अपने भीतर उस दिव्य शक्ति का अनुभव करने का प्रयास करते थे। उनके माता-पिता और परिवारजन उनके इस स्वभाव को देखकर आश्चर्यचकित होते थे, क्योंकि इतनी छोटी आयु में ही उनका झुकाव पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन की ओर था।

समय बीतने के साथ उनकी भक्ति और भी प्रगाढ़ होती गई। जब उनकी बहन कान्ही बाई अपने पुत्र उदयराम के साथ सालासर में रहने लगीं, तो मोहनदास जी भी उनके साथ वहाँ आ गए। सालासर का शांत वातावरण, सरल जीवन और आध्यात्मिक ऊर्जा उनके लिए अत्यंत उपयुक्त सिद्ध हुआ। यहाँ आकर उन्होंने अपना अधिकांश समय भगवान की साधना में व्यतीत करना शुरू कर दिया। उनका मन अब पूरी तरह से सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुका था और वे केवल अपने आराध्य की भक्ति में डूबे रहते थे।

एक दिन खेत में कार्य करते समय उनके साथ एक अद्भुत घटना घटी। उनके हाथ से गंडासी बार-बार छूटकर गिरने लगी। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। जब उनके भानजे उदयराम ने इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें यह संकेत दे रही है कि उनका जीवन सांसारिक कार्यों के लिए नहीं, बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए बना है। यह अनुभव उनके जीवन का निर्णायक क्षण बन गया। परिवार के लोगों ने उन्हें सामान्य जीवन में वापस लाने का प्रयास किया और उनका विवाह तय करने की योजना बनाई। लेकिन मोहनदास जी का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था।

उन्होंने गहरी भावना से कहा कि इस संसार में हर स्त्री किसी न किसी रूप में पूजनीय है। जो स्त्री आयु में बड़ी है, वह माता के समान है, जो समान आयु की है, वह बहन के समान है और जो छोटी है, वह पुत्री के समान है। ऐसे में विवाह का विचार उनके लिए असंभव था। उनके इस विचार ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे अब सांसारिक जीवन से पूरी तरह विरक्त हो चुके हैं। उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और अपना संपूर्ण जीवन भगवान की भक्ति को समर्पित कर दिया।

उनकी भक्ति की शक्ति इतनी प्रबल थी कि एक दिन स्वयं हनुमान जी ने साधु के वेश में उन्हें दर्शन दिए। यह क्षण उनके जीवन का सबसे महान और दिव्य अनुभव था। जब उन्होंने उस साधु रूप में प्रभु को देखा, तो वे भावविभोर हो उठे और उनके पीछे चल पड़े। प्रभु ने उनसे पूछा कि वे क्या चाहते हैं। मोहनदास जी ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया कि उन्हें किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रभु का सान्निध्य ही उनके लिए सबसे बड़ा वरदान है। उनकी इस निष्काम भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें वरदान देने की इच्छा प्रकट की। तब मोहनदास जी ने प्रार्थना की कि प्रभु सालासर में निवास करें, ताकि सभी भक्त उनके दर्शन कर सकें और उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। प्रभु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वचन दिया कि वे मूर्ति रूप में सालासर में प्रकट होंगे। यह वचन केवल एक आशीर्वाद नहीं था, बल्कि एक दिव्य भविष्यवाणी थी, जो आगे चलकर सत्य सिद्ध हुई।

कुछ समय बाद आसोटा गाँव में एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसका हल भूमि में किसी कठोर वस्तु से टकराया। जब उस स्थान की खुदाई की गई, तो वहाँ से भगवान हनुमान की एक दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। यह दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह कोई सामान्य मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक अलौकिक स्वरूप था, जिसमें प्रभु की दिव्यता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। यह समाचार पूरे क्षेत्र में फैल गया और लोग इस चमत्कार को देखने के लिए उमड़ पड़े।

मूर्ति को अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ सालासर लाया गया। महात्मा मोहनदास जी ने निर्देश दिया कि मूर्ति को उस स्थान पर स्थापित किया जाए जहाँ बैल स्वयं रुक जाएँ। जब बैल एक रेत के टीले पर जाकर रुक गए, तो इसे प्रभु की इच्छा का संकेत माना गया। उसी स्थान पर विधिपूर्वक मूर्ति की स्थापना की गई। यह दिन भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक बन गया।

मंदिर का निर्माण कार्य भी अत्यंत विशेष था। इसमें विभिन्न धर्मों के लोगों ने मिलकर योगदान दिया। मुस्लिम कारीगरों ने भी मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि भक्ति और आस्था किसी एक धर्म की सीमा में बंधी नहीं होती, बल्कि यह मानवता की साझा विरासत है। यह मंदिर आज भी धार्मिक सद्भाव और एकता का प्रतीक बना हुआ है।

मंदिर में प्रज्वलित अखंड ज्योति सदियों से निरंतर जल रही है। यह ज्योति भक्तों के अटूट विश्वास और प्रभु की कृपा का प्रतीक है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु नारियल बांधकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और भक्तों का विश्वास है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य पूर्ण होती है।

आज सालासर बालाजी धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का जीवंत केंद्र बन चुका है। यहाँ आने वाला हर भक्त एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव करता है। यह स्थान भक्तों को यह विश्वास दिलाता है कि जब भक्ति सच्ची होती है, तो प्रभु स्वयं अपने भक्त के पास आ जाते हैं।

सालासर धाम की महिमा केवल उसकी ऐतिहासिकता या चमत्कारों में ही नहीं, बल्कि उस आध्यात्मिक ऊर्जा में है, जो हर भक्त के हृदय को स्पर्श करती है। यह धाम हमें यह सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से जीवन के सबसे कठिन संकट भी दूर हो सकते हैं। यहाँ का वातावरण, यहाँ की भक्ति और यहाँ का विश्वास हर व्यक्ति को यह अनुभव कराता है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में निवास करते हैं, जहाँ सच्ची भक्ति और प्रेम होता है।

इसी कारण सालासर बालाजी धाम आज भी आस्था का वह अमर दीप बना हुआ है, जो सदियों से भक्तों के जीवन को प्रकाश और आशा से भर रहा है, और आने वाले अनंत समय तक इसी प्रकार मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

साणंद से भारत की टेक क्रांति के नए अध्याय का प्रारंभ

साणंद में माइक्रोन सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कराया

साणंद बनेगा देश में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का प्रवेश द्वार : 22,516 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एआई टेक्नोलॉजी के भविष्य को मिलेगी नई ताकत

▸▸ श्री सोमनाथ मंदिर पर 1500 से अधिक कलश स्वर्ण जड़ित हुए

▸▸ सोमनाथ मंदिर का गर्भगृह, गर्भगृह के द्वार तथा द्वार के पास के स्तंभ, थाल आदि स्वर्ण से अलंकृत

▸▸ श्री सोमनाथ मंदिर के शिखर पर स्थापित ध्वदंड और उसके साथ जुड़ा त्रिशूल भी है स्वर्ण जड़ित

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इतिहास पुराणों में वर्णित सोमनाथ का वैभव पुनः स्थापित हो रहा है : इतिहासप्रेमी तथा अध्ययनी श्री भास्करभाई वैद्य

▸▸ प्रधानमंत्री तथा सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र मोदी के दिशादर्शन में पुनः स्थापित हो रही सोमनाथ की पौराणिक वैभवता तथा भव्यता

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

▸▸ 20वीं शताब्दी का रेगुलेटर ऑइल था, 21वीं शताब्दी का रेगुलेटर माइक्रोचिप बनेगी

▸▸ इंडिया ईज रेडी, इंडिया ईज रिलायेबल एंड इंडिया डिलीवर्स

▸▸ यह दशक भारत के टेक फ्यूचर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगा

▸▸ सॉफ्टवेयर के लिए विख्यात भारत अब हार्डवेयर के क्षेत्र में भी अपनी पहचन सशक्त कर रहा है

▸▸ साणंद आज ग्लोबल मैप पर सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभर रहा है

मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल

▸▸ गुजरात एआई तथा सेमीकंडक्टर जैसे उभरते सेक्टर में भी 'ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर' बनने की ओर आगे बढ़ रहा है

▸▸ गुजरात वर्ष 2022 में सेमीकंडक्टर पॉलिसी घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य

▸▸ केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की प्रोत्साहक उपस्थिति

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को अहमदाबाद के साणंद में माइक्रोन सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का शुभारंभ कराते हुए कहा कि 20वीं शताब्दी का रेगुलेटर ऑइल था, जबकि 21वीं शताब्दी का रेगुलेटर माइक्रोचिप बनेगी। उन्होंने कहा कि यह एआई रिवॉल्यूशन की सदी है। समग्र विश्व में भारत आज कैपेबल, कमीटिटेव तथा कमिटेड मित्र एवं भागीदार के रूप में उभर रहा है। लगभग 22,516 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के साथ गुजरात अब देश के 'सेमीकंडक्टर हब' के रूप में पहचान स्थापित करेगा।

प्रधानमंत्री ने साणंद से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हुए भारत के भावी उदय का रोडमैप दर्शाते हुए कहा कि सॉफ्टवेयर के लिए विख्यात भारत अब हार्डवेयर क्षेत्र में भी अपना पहचान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अत्यंत तेजी से वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का हिस्सा बन रहा है। इस अवसर पर श्री मोदी ने समग्र विश्व को विश्वास दिलाते हुए कहा कि भारत इंडिया ईज रेडी, इंडिया ईज रिलायेबल एंड इंडिया डिलीवर्स।

इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी के अत्याधुनिक एटीएमपी (असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग तथा पैकेजिंग) प्लांट के कामकाज और अन्य विवरण दर्शाने वाली प्रदर्शनी को देखा तथा प्लांट की मुलाकात लेकर सेमीकंडक्टर चिप के असेम्बली व पैकेजिंग के विभिन्न ऑपरेशन्स के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन अंतर्गत माइक्रोन फैसिलिटी द्वारा इस प्लांट का निर्माण किया गया है।

इससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने साणंद जीआईडीसी में आयोजित रोड शो अंतर्गत उपस्थित जनसैलाब का अभिवादन स्वीकार किया। कार्यक्रम में माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा डेल टेक्नोलॉजी के प्रथम कॉमर्शियल मेड इन इंडिया शिपमेंट को प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हैंडओवर किया गया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी एवं सफल एआई समिट के बाद आज हम टेक्नोलॉजी लीडरशिप क्षेत्र में भारत की कटिबद्धता के एक ऐतिहासिक पड़ाव के साक्षी बने हैं। 10-11 वर्ष पहले तक भारत मे डेटा व चिप की चर्चा केवल सीमित वर्गों में ही होती थी और टेक्नोलॉजी के नाम पर हम केवल आईटी सर्विसेज तक सीमित थे, परंतु आज सॉफ्टवेयर के लिए विख्यात भारत अब हार्डवेयर क्षेत्र में भी अपनी पहचान सशक्त कर रहा है।

उन्होंने प्रोजेक्ट की गतिशीलता पर बल देते हुए इस बात को ध्यान में लिया कि जून-2023 में इस सुविधा के लिए एमओयू हुआ, सितंबर में शिलान्यास हुआ और आज फरवरी-2026 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है। विश्व के विकसित देशों में भी ऐसी मंजूरियों एवं प्रक्रियाओं में वर्षों निकल जाया करते हैं, परंतु भारत ने यह असंभव कार्य केवल 900 दिनों में पूरा करके बताया है। जब दानत साफ हो और निष्ठा देश के तेज विकास के प्रति हो, तब नीति स्पष्ट बनती है और निर्णयों में भी गति अपने आप आ जाया करती है।

प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तथा एआई रिवॉल्यूशन को जोड़ने वाला सबसे बड़ा सेतु बताया। उन्होंने कहा कि भारत अब इस वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। उन्होंने जोड़ा कि कोविड के मुश्किल समय में बोए गए बीज आज वटवृक्ष बनकर फल दे रहे हैं तथा अब तक सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम अंतर्गत 10 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है।

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि हमारा लक्ष्य केवल एक फैक्ट्री स्थापित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण इकोसिस्टम बनाने का है। भारत अब सेमीकंडक्टर की पूरी वैल्यू चेन पर फोकस कर रहा है, जिसमें डिजाइन इंजीनियर से लेकर मशीन निर्माता तथा लॉजिस्टिक्स तक के सभी स्तर शामिल हैं। 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' की घोषणा इसी दिशा में उठाया गया कदम है। जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ेगा, वैसे-वैसे भारत के भीतर ही मटीरियल तथा कम्पोनेंट्स की मांग बढ़ेगी, जो स्थानीय उद्योगों के लिए सबसे बड़ा अवसर सिद्ध होगा।

भारत के बढ़ते जा रहे मार्केट की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स तथा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत की मांग निरंतर बढ़ रही है। इसलिए 'मेक इन इंडिया' अब फुल स्विंग में आगे बढ़ रहा है। पिछले 11 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन तथा उसके निर्यात में अनेक गुना वृद्धि हुई है। भारत अब कम्पोनेंट से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट तक सभी कुछ देश में बनाने के लिए सज्ज है, जो वैश्विक निवेशकों के लिए घरेलू बाजार एवं वैश्विक अवसर; दोनों प्रदान करता है।

साणंद के साथ अपने निजी संस्मरणों को ताजा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि साणंद तो ऐसी धरती है, जो मिट्टी को भी सोना बना देती है। उन्होंने याद किया कि वे यहाँ एक समय किस तरह साइकिल पर घूमते थे और एक रुपए के एसएमएस से यहाँ रतन टाटा के प्लांट के साथ ऑटोमोबाइल क्रांति की शुरुआत हुई थी। आज वही साणंद ग्लोबल मैप पर सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री ने यहाँ काम करने के लिए आने वाले देश-विदेश के तकनीशियनों को आश्वस्त किया कि गुजरात सरकार उन्हें श्रेष्ठ जीवनशैली तथा सुविधाएँ प्रदान करने में कोई कमी नहीं रखेगी।

पर्यावरण एवं टेक्नोलॉजी के समन्वय के बारे में चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने माइक्रोन के प्लांट की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यहाँ बनाया गया 'क्लीन रूम स्पेस' विश्व के सबसे बड़े स्पेस में एक है। साथ ही; प्लांट में पानी के कम से कम उपयोग तथा रिसाइकलिंग के लिए जो व्यवस्थाएं की गईं हैं, वे प्रगति एवं प्रकृति के तालमेल का श्रेष्ठ उदाहरण हैं। उन्होंने गुजरात सरकार की प्रो-एक्टिव नीतियों की भी सराहना की, जिसके कारण निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है।

संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व को मजबूत संदेश देते हुए कहा कि जब भावी पीढ़ियाँ इस दशक को पीछे मुड़कर देखेंगी, तब वे गौरव के साथ कहेंगी कि इस दशक में भारत ने कितनी ऊंची छलांग लगाई थी। यह दशक भारत के टेक फ्यूचर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आश्वासन दिया कि भारत सरकार तथा राज्य सरकारें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने साणंद में माइक्रोन प्लांट के लोकार्पण को सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम क्षेत्र में नींव का पत्थर बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज गुजरात ग्लोबल मैप पर ग्रोथ इंजन के रूप में चमका है। साणंद और धोलेरा सेमीकंडक्टर फैसिलिटी प्लांट के मुख्य केंद्र बनकर उभरे हैं। प्रधानमंत्री के अथक परिश्रम और राज्य की उद्यमिता के कारण ही लार्ज स्केल और जेट स्पीड से इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि यह विकास यात्रा केवल नए उद्योग की शुरुआत ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के देशों के लिए एक भरोसेमंद मित्र के रूप में 'नए भारत' की पहचान भी है। मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट की अभूतपूर्व गति और कार्यक्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जून 2023 में प्रधानमंत्री के वाशिंगटन दौरे के दौरान इस प्रोजेक्ट की घोषणा हुई थी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा 15 जून 2023 को इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के केवल 24 घंटे के भीतर ही गुजरात सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। ऐसी तेजी केवल गुजरात में ही संभव है, क्योंकि हम प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित बेंचमार्क और 'आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर गुजरात' के मंत्र के साथ काम करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सेमीकंडक्टर चिप्स आज डिजिटल युग की रीढ़ है। मोबाइल, ऑटोमोबाइल, डिफेंस, स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे हरेक क्षेत्र में इसकी जरूरत है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सेमीकंडक्टर मिशन, पीएलआई योजना और 'मेक इन इंडिया' जैसी पहलों के चलते भारत दुनिया में एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात वर्ष 2022 में सेमीकंडक्टर पॉलिसी घोषित करने वाला देश का पहला राज्य था। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल, डायमंड और फार्मा जैसे परंपरागत क्षेत्रों में अग्रणी रहने के बाद अब गुजरात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और सेमीकंडक्टर जैसे उभरते सेक्टरों में भी 'ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर' बनने जा रहा है। माइक्रोन का यह प्लांट न केवल एक औद्योगिक परियोजना है, बल्कि युवाओं के सपनों का इन्वेस्टमेंट भी है। उन्होंने कहा कि गुजरात 'मेक इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड' के मंत्र के साथ विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए कटिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इस दिन को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि भारत ने पिछले छह दशकों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में जो स्वप्न देखा था, वह आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मजबूत संकल्प से साकार हुआ है। केवल 900 दिनों में फाउंडेशन से प्रोडक्शन तक का यह सफर 'मोदी है तो मुमकिन है' के नारे को चरितार्थ करता है। उन्होंने आगे कहा कि सेमीकंडक्टर एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। मोबाइल, लैपटॉप या सर्वर, सभी उपकरणों के लिए यह चिप्स अनिवार्य है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में पिछले एक दशक में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में छह गुना और निर्यात में आठ गुना वृद्धि हुई है। अब 'सेमीकंडक्टर 2.0' के माध्यम से हम केवल चिप डिजाइन ही नहीं, बल्कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग, मशीनरी, केमिकल्स और गैस सहित संपूर्ण इकोसिस्टम भारत में ही तैयार करने जा रहे हैं। आज देश की 315 से अधिक यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थी चिप डिजाइन कर रहे हैं, जो विकसित भारत की मजबूत नींव की निशानी है। भारत में यूएस के राजदूत श्री सर्जियो गोर ने इस अवसर को भारत-अमेरिका के मजबूत संबंधों का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह प्लांट केवल एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी और भारतीय मैन्युफैक्चरिंग उत्कृष्टता के समन्वय का भविष्य है। उन्होंने इस अवसर पर अमेरिकी प्रशासन के सहयोग का उल्लेख करते हुए दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प के रूप में उभरा है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की भूमिका अब अनिवार्य बन गई है। गुजरात आज साणंद से लेकर धोलेरा तक, सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए जो वातावरण प्रदान कर रहा है, वह अन्य देशों और निवेशकों के लिए एक सफल मॉडल है। अमेरिकन कंपनियां गुजरात में मौजूद इन अवसरों को बहुत ही सकारात्मक तरीके से देख रही हैं। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ श्री संजय मेहरोत्रा ने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए भावुक स्वर में कहा, "यह केवल एक उद्घाटन समारोह नहीं, बल्कि इतिहास का एक अमर क्षण है। दिल्ली के सरदार पटेल विद्यालय में पढ़ाई के दौरान लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के दृढ़ संकल्प से मुझे जो प्रेरणा मिली थी, आज साणंद की इस धरती पर उस संकल्प को साकार होते हुए देख रहा हूं। मुझे विश्वास था कि जो कभी नहीं बना, वह हम बना सकते हैं और आज हमने साणंद में वह कर दिखाया है।" उन्होंने भारत को सेमीकंडक्टर मैप पर अंकित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजनरी नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि एआई के युग में डेटा ही हृदय के समान है और डेटा के लिए मेमोरी और स्टोरेज अनिवार्य है। माइक्रोन का यह प्लांट प्रतिवर्ष करोडों की संख्या में चिप का उत्पादन करके वैश्विक जरूरतों को पूरी करेगा। हम यहां केवल उत्पादन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि 100 फीसदी वाटर री-यूज और सस्टेनेबिलिटी के साथ पर्यावरण का संरक्षण भी कर रहे हैं। भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने गुजराती में गर्व के साथ कहा, "जब लोग पूछते हैं कि क्या भारत में विश्व स्तरीय सेमीकंडक्टर फैसिलिटी बन सकती है?" तब मेरा जवाब होता है, "हां, यह संभव है!" उल्लेखनीय है कि माइक्रोन के मेगा सेमीकंडक्टर प्लांट में एसएसडी (सॉलिड स्टेट ड्राइव), डीआरएएम और एनएएनडी जैसे आधुनिक स्टोरेज और मेमोरी उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। ये उत्पाद विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के युग में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि मजबूत मेमोरी सपोर्ट के बिना एआई प्रणाली कुशलता से काम नहीं कर सकती। माइक्रोन का यह प्लांट दुनिया के सबसे बड़े और अत्यंत स्वच्छ 'क्लीन रूम' वाली इकाइयों में से एक है, जहां ऑपरेशन थियेटर से भी अधिक शुद्ध वातावरण में चिप की पैकेजिंग की जाती है। रोजगार के क्षेत्र में भी यह प्लांट आशा की एक नई किरण लेकर आया है। वर्तमान में यहां 2000 लोगों की टीम कार्यरत है, जो आगामी समय में बढ़कर 5000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार तक पहुंच जाएगी।

सूरत में वाल्मीकि समुदाय के नेताओं ने पिथावाला से मुलाकात कर अभिवादन किया और एकता पर जोर दिया

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। कोली समुदाय के लोकप्रिय और अनुभवी गांधीवादी नेता, माननीय चंद्रवदनभाई पिथावाला साहब ने 28 फरवरी 2026 को सूरत में वाल्मीकि समाज के नेताओं श्यामभाई तेनिया (महासचिव), रविकुमार सुरती (महासचिव और गायक), मनीषभाई राजवाड़ी संगीतकार, अश्विन बी. वैष्णव (अधिवक्ता और नोटरी), ची वंश (गुजरात प्रदेश नगर निगम कर्मचारी) और कांग्रेस एवं समाज गुजरात के अध्यक्ष भाई लाल बी. वैष्णव के कार्यालय का दौरा किया और समाज की प्रगति के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया। पिथावाला साहब ने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति के लिए समाज की एकता और मजबूत संगठन आवश्यक है । समाज में राजनीति नहीं लानी चाहिए। समाज में राजनीति हो सकती है, लेकिन राजनीति को समाज में नहीं लाना चाहिए। समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ाने और समाज को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए कि समाज के जरूरतमंद लोगों को राशन कार्ड, आधार कार्ड, जातिगत पहचान पत्र और शिक्षा आसानी से मिल सके। समाज में अच्छी प्रतिष्ठा और विश्वास रखने वाले लोगों को समाज का नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए। समाज के उत्थान के लिए वाल्मीकि द्वारा दिए गए परामर्श से नेता अत्यंत प्रभावित हुए। समाज के नेताओं ने पीठावला साहब को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर आभार व्यक्त किया।

जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर सवाल उठे, ईडी की निष्पक्षता पर सवाल उठे

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सरकार की कुछ जांच एजेंसियों, जैसे सीबीआई और ईडी, को धन शोधन जैसे आर्थिक अपराधों की जांच करने का अधिकार है। इनमें से कुछ सरकारी विभागों या जांच एजेंसियों की प्रतिष्ठा न केवल सरकार के लिए बल्कि देश या राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए, सीबीआई, ईडी या चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं की अतीत में एक अलग ही प्रतिष्ठा थी। उनकी एक विशेष पहचान थी। लेकिन अब जिस तरह से ये संस्थाएं सरकार के इशारे पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाकर काम कर रही हैं, उससे जनता के बीच इनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है।

शून्य त्रुटि विज्ञापन

यहां यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि एक मामले की सुनवाई के दौरान मद्रास उच्च न्यायालय ने स्पष्ट टिप्पणी की थी कि ईडी कोई "ड्रोन" नहीं है जो आपराधिक गतिविधि का पता चलते ही हमला कर दे। न्यायालय ने यह भी कहा कि जांच एजेंसी किसी उच्च कुशल पुलिस अधिकारी (सुपर कॉप) की तरह नहीं है जो हर मामले की जांच करे। हर जांच एजेंसी के कामकाज में कुछ कमियां होती हैं। लेकिन जब उसके खिलाफ इतने सारे सवाल उठने लगते हैं, तो यह उसकी प्रतिष्ठा पर एक धब्बा जैसा होता है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी से जुड़े भूखंड आवंटन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी है कि राजनीतिक लड़ाई मतदाताओं के साथ लड़ी जानी चाहिए। इसमें ईडी जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से, लगातार उठते सवालों के बीच, ईडी को अपने काम में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम करना चाहिए, ताकि उसकी विश्वसनीयता धूमिल न हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईडी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम करने का साहस दिखाएगी? इससे यह साबित होता है कि देश में विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सरकार की जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के विपक्ष के आरोप सही हैं। और इसका ताजा उदाहरण केजरीवाल और मनोज सिसोदिया मामले का फैसला है।

गोवा से संचालित ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क का पर्दाफाश, 431 बैंक खातों का इस्तेमाल उजागर

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा और उससे जुड़े अंतरराज्यीय पेमेंट गेट-वे नेटवर्क का बड़ा खुलासा करते हुए सात आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की एण्टी क्राइम एवं साइबर यूनिट और न्यू राजेन्द्र नगर थाना की संयुक्त टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गिरफ्तार आरोपितों में दो आरोपी रायपुर से और पांच आरोपी गोवा से पकड़े गए हैं। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैंकिंग दस्तावेज और अन्य सामग्री बरामद की है, जिससे एक संगठित ऑनलाइन सट्टा गिरोह के संचालन का खुलासा हुआ है।

क्राइम एवं साइबर पुलिस के उपायुक्त स्मृतिक राजनाला के अनुसार, 25 फरवरी 2026 को पुलिस को सूचना मिली थी कि न्यू राजेन्द्र नगर क्षेत्र में मुक्तिधाम के पास एक वाहन से ऑनलाइन सट्टा संचालित किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन में मौजूद दो संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया। जब उनसे पूछताछ की गई, तो उन्होंने स्वीकार किया कि वे ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क से जुड़े हैं और उनके अन्य सहयोगी गोवा से पूरे सट्टा पैनल और पेमेंट गेट-वे का संचालन कर रहे हैं। इस खुलासे के बाद पुलिस टीम ने गोवा में छापेमारी कर इस नेटवर्क से जुड़े कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि इस गिरोह ने अवैध लेन-देन के लिए 431 म्यूल बैंक खातों का उपयोग किया था। ये बैंक खाते अलग-अलग व्यक्तियों के नाम पर खोले गए थे और इनके माध्यम से करोड़ों रुपये का लेन-देन किया जा रहा था। पुलिस अब इन खातों की विस्तृत जानकारी एकत्र कर रही है और उनसे जुड़े मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि इस नेटवर्क में शामिल अन्य संदिग्धों की पहचान भी की जा रही है और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपित विभिन्न ऑनलाइन बैटिंग वेबसाइटों के मास्टर आईडी कमीशन के आधार पर उपलब्ध कराते थे। इसके अलावा वे व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से पेमेंट गेट-वे का संचालन करते थे और ग्राहकों के पैसे जमा करने और निकालने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते थे। यह पूरा नेटवर्क अत्यंत संगठित तरीके से काम कर रहा था, जिसमें तकनीकी उपकरणों और डिजिटल प्लेटफॉर्म का व्यापक उपयोग किया जा रहा था।

जांच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि आरोपित अवैध रूप से अर्जित धनराशि को छिपाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग कर रहे थे। पुलिस के अनुसार, अब तक लगभग 46,500 यूएसडीटी, जिसकी भारतीय मुद्रा में अनुमानित कीमत करीब 42 लाख रुपये है, को क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांसफर किए जाने के प्रमाण मिले हैं। क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग से इस नेटवर्क ने अपनी पहचान और लेन-देन को छिपाने का प्रयास किया, जिससे जांच और भी जटिल हो गई है। साइबर विशेषज्ञों की मदद से अब इन डिजिटल लेन-देन की गहन जांच की जा रही है।

पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक और बैंकिंग उपकरण बरामद किए हैं। जब्त सामग्री में 24,600 रुपये नकद, पांच लैपटॉप, एक टैबलेट, 58 मोबाइल फोन, 12 एटीएम कार्ड, तीन इंटरनेट राउटर, चार बैंक पासबुक और एक कार शामिल है। जब्त की गई कुल सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग 22.14 लाख रुपये बताई गई है। इन उपकरणों का उपयोग सट्टा संचालन, भुगतान प्रक्रिया और नेटवर्क के प्रबंधन के लिए किया जा रहा था।

इस मामले में आरोपितों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022 और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई राज्य में ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान का हिस्सा है। वर्ष 2026 में अब तक साइबर यूनिट द्वारा ऑनलाइन सट्टा से जुड़े पांच मामलों में कुल 22 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है और लगभग 2.14 करोड़ रुपये की संपत्ति और नकदी जब्त की गई है।

पुलिस के अनुसार, ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क तेजी से फैल रहा है और इसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे इसे पकड़ना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हालांकि, साइबर यूनिट की सक्रियता और तकनीकी विशेषज्ञता के कारण ऐसे नेटवर्क का लगातार खुलासा किया जा रहा है। अधिकारियों ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे इस तरह की अवैध गतिविधियों से दूर रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।

भावनगर मंडल रेलवे अस्पताल में अधिकारियों हेतु विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का सफल आयोजन

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल स्थित मंडल रेलवे अस्पताल (DRH), भावनगर द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2026 (शनिवार) को अस्पताल परिसर में मंडल के अधिकारियों हेतु एक विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों में निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, जीवनशैली से संबंधित रोगों की समय रहते पहचान करना तथा नियमित चिकित्सकीय परामर्श के माध्यम से उनके समग्र स्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता को सुदृढ़ करना था।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार आज की व्यस्त एवं तनावपूर्ण जीवनशैली, अनियमित दिनचर्या तथा कार्यस्थल के दबाव के कारण उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग एवं मोटापे जैसी जीवनशैली संबंधी बीमारियों का जोखिम लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में इस प्रकार के स्वास्थ्य जांच शिविर संभावित रोगों की प्रारंभिक पहचान एवं समय पर उपचार सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

शिविर के दौरान अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री ऋत्विक शर्मा सहित अन्य अधिकारियों को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं, जिनमें रक्तचाप (बीपी) जांच, आवश्यक रक्त परीक्षण, बीएमआई एवं वजन आकलन, सामान्य चिकित्सक परामर्श तथा निवारक स्वास्थ्य एवं स्वस्थ जीवनशैली संबंधी मार्गदर्शन शामिल रहा। अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक शिविर में भाग लिया तथा चिकित्सा विभाग की इस सराहनीय पहल की प्रशंसा की।

शिविर का संचालन मंडल रेलवे अस्पताल, भावनगर के मंडल चिकित्सा अधिकारी एवं एमडी फिजिशियन डॉ. प्रतीक वोरा के चिकित्सकीय पर्यवेक्षण में उनकी समर्पित चिकित्सा टीम द्वारा सुव्यवस्थित एवं कुशलतापूर्वक किया गया।

यह कार्यक्रम मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनोज कुमार के समग्र मार्गदर्शन में आयोजित किया गया, जिनके नेतृत्व एवं सहयोग से शिविर का सफल क्रियान्वयन संभव हो सका। साथ ही एएनओ, भावनगर द्वारा पूरे कार्यक्रम का प्रभावी समन्वय एवं प्रबंधन सुनिश्चित किया गया।

भावनगर मंडल रेलवे अस्पताल प्रशासन ने भविष्य में भी इस प्रकार के स्वास्थ्य जागरूकता एवं निवारक चिकित्सा कार्यक्रमों के आयोजन की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जिससे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं कल्याण को निरंतर प्रोत्साहन मिल सके।

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND OTHER PARTICULARS
ABOUT NEWSPAPER "NAVSARJAN SANSKRUTI"
HINDI DAILY AS REQUIRED TO BE PUBLISHED
UNDER RULE 8 OF REGISTRATION OF NEWS PAPER.
(CENTRAL RULES 1856)
FORM - IV
(SEE RULE - 8)

1. Place of Publication — **B/13,**Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, **Chandkheda, Ahmedabad- 382 424,Gujarat, India.**
2. Periodicity of its publication — Gujarati Daily
3. Printer's name — **(1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR** **(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI** **(3) HARDIK MAHESHBHAI DESHI**
   Whether Citizen of India ? Yes
   Address — **(1)Vansh Corporation,** A/8, Shayona Golden **Estate,Shahibag,Ahmedabad-380004,Gujarat, India.** **(2)BhavaniOffset,BhatiyaNi Wadi,Opp.KalupurRailway Station,Kalupur,Ahmedabad-380002.Gujarat, India.** **(3)BhoomiOffset,BhatiyaNi Wadi,Opp.KalupurRailway Station,Kalupur,Ahmedabad-380002.Gujarat, India.**
4. Publisher's name — **RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA** **F/102,**Tulsi Residency,Mansarover Road,IOC, **Chandkheda, Ahmedabad- 3802 424,Gujarat, India.**
5. Editor's name — **JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA**
   Whether Citizen of India ? Yes
   Address — **F/102,**Tulsi Residency,Mansarover Road,IOC, **Chandkheda, Ahmedabad- 3802 424,Gujarat, India.**
6. Owners Names And Address — **RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA** **F/102,**Tulsi Residency,Mansarover Road,IOC, **Chandkheda, Ahmedabad- 3802 424,Gujarat, India.**

I **RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA** here by declare that particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Date : 01-03-2026

Ragini Jigneshkumar Vaghela
Singaturs of Publisher.

जस्टिस सूर्यकांत और भूपेंद्र पटेल ने गुजरात हाई कोर्ट के नए स्टेट ऑफ-द-आर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर के भवन की आधारशिला रखी

▸▸ गुजरात हाई कोर्ट में 'संस्थागत मध्यस्थता की चुनौतियां और भावी दिशा' विषय पर दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ

▸▸ राज्य सरकार 'सभी के लिए न्याय, समय पर न्याय' के दृष्टिकोण के साथ न्यायिक ढांचागत सुविधाओं को मजबूत बनाने को कटिबद्ध : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ मध्यस्थता के क्षेत्र में नवीन सुविधाओं से भारत की मध्यस्थता व्यवस्था और भी सक्षम, विश्वसनीय और आधुनिक बनेगी : मुख्य न्यायमूर्ति श्री जस्टिस सूर्यकांत

▸▸ सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सर्वश्री जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस एन.वी. अंजारिया, जस्टिस विपुल पंचोली, गुजरात के उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश श्रीमती सुनीता अग्रवाल सहित न्यायमूर्तियों की प्रोत्साहक उपस्थिति

▸▸ आर्बिट्रेशन सेंटर के लोगो, री-डिजाइन की गई नई वेबसाइट और न्यूजलेटर का विमोचन

गांधीनगर : सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को अहमदाबाद में गुजरात हाई कोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर (मध्यस्थता केंद्र) के नए अत्याधुनिक भवन की आधारशिला रखी, और सेंटर के लोगो का अनावरण भी किया।

इसके साथ ही, गुजरात हाई कोर्ट सभागार में 'इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन एट अ क्रॉसरोड्स : चैलेंजेस एंड द वे फॉरवर्ड' विषय पर एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस का भी प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर मध्यस्थता केंद्र के न्यूजलेटर का विमोचन और केंद्र की री-डिजाइन की गई नई वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया।

इस कार्यक्रम का आयोजन गुजरात हाई कोर्ट मध्यस्थता केंद्र और गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान तथा गुजरात हाई कोर्ट के मार्गदर्शन में किया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) माननीय श्री सूर्यकांत ने अपने संबोधन में कहा कि गुजरात हाई कोर्ट मध्यस्थता केंद्र के नए अत्याधुनिक भवन का शिलान्यास और संस्थागत मध्यस्थता के भविष्य पर आयोजित हो रही कॉन्फ्रेंस देश के विवाद समाधान ढांचे को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

उन्होंने बलपूर्वक कहा कि भौतिक बुनियादी ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर) केवल एक प्रशासनिक सुविधा नहीं है, बल्कि यह संस्था की गंभीरता और विश्वसनीयता का संकेत है। जब कोई अंतरराष्ट्रीय निवेशक या पक्षकार पेशेवर एवं सुविधाजनक मध्यस्थता केंद्र में प्रवेश करता है, तो उसे यह भरोसा होता है कि उसके विवाद का उचित एवं तटस्थ निराकरण होगा। मुख्य न्यायमूर्ति ने आगे कहा कि गुजरात औद्योगिक विकास और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश में अग्रणी है, तब विदेशी निवेशकों के लिए परंपरागत कानूनी प्रक्रिया की तुलना में संस्थागत मध्यस्थता अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

उन्होंने इस क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों के बारे में स्पष्टता करते हुए कहा कि हमें केवल कागज पर दिए गए नियमों से ही नहीं, अपितु पारदर्शी और न्यायी प्रक्रिया के माध्यम से पक्षकारों का भरोसा जीतना होगा। भारत को मध्यस्थों की गुणवत्ता और प्रशिक्षण में निवेश करने की जरूरत है, ताकि भारत वैश्विक स्तर के मध्यस्थता केंद्र के तौर पर उभर सके। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, नई वेबसाइट और न्यूजलेटर की लॉन्चिंग की सराहना करते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि इन नई सुविधाओं से भारत की मध्यस्थता प्रणाली और भी सक्षम, विश्वसनीय एवं आधुनिक बनेगी।

गुजरात हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति और गुजरात हाई कोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर (जीएचएसी) के अध्यक्ष तथा गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (जीएसएलएसए) के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.वाई. कोगजे, गुजरात हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति और बिल्डिंग कमेटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति श्री ए.एस. सुपेहिया, राज्य के महाधिवक्ता श्री कमल त्रिवेदी सहित गुजरात हाई कोर्ट के अन्य न्यायमूर्ति उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश को 'ग्लोबल आर्बिट्रेशन हब' यानी वैश्विक मध्यस्थता का हब बनाने के संकल्प के साथ न्याय प्रक्रिया में अनेक सुधार किए जा रहे हैं, जिसमें आज गुजरात के न्याय तंत्र के लिए एक नया ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है।

भारत में मध्यस्थता की परंपरा के सदियों पुरानी होने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता की जड़ें उपनिषदों में वर्णित मध्यस्थता संस्थाओं और पंचायत प्रणाली की 'पंच परमेश्वर' की भावना से ही जुड़ी हैं। पूज्य महात्मा गांधी जी के उदाहरण के साथ उन्होंने कहा कि एक वकील का वास्तविक कार्य दो विभाजित पक्षों को एक करना है और यह विचारधारा वर्तमान मध्यस्थता प्रणाली का हार्द है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार 'सभी के लिए न्याय, समय पर न्याय' के दृष्टिकोण के साथ न्यायिक ढांचागत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कटिबद्ध है। हाल ही में पेश किए गए राज्य सरकार के बजट में इस उद्देश्य से विधि विभाग के लिए 2700 करोड़ रुपए से अधिक की बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि गुजरात व्यापार और उद्योग क्षेत्र में वैश्विक निवेश का एक अग्रणी राज्य होने के कारण त्वरित विवाद निवारण के लिए मध्यस्थता जैसी प्रणाली 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' यानी कारोबार करने की सुगमता को मजबूत आधार देगी।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यहां आकार लेने वाली स्टेट-ऑफ-द-आर्ट इमारत और लॉन्च की गई नई वेबसाइट मध्यस्थता प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाएगी और यह 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का आधार सिद्ध होगी।

इस कार्यक्रम के मेजबान के रूप में गुजरात हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश श्रीमती सुनीता अग्रवाल ने स्वागत भाषण में सभी का स्वागत-सत्कार किया। उन्होंने यहां निर्मित होने वाले स्टेट-ऑफ-द-आर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर के बारे में, उसमें उपलब्ध होने वाली सुविधाओं, सेंटर की आवश्यकता तथा उसके निर्माण एवं सेंटर की री-डिजाइन की गई नई वेबसाइट सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जस्टिस श्री अरविंद कुमार, जस्टिस श्री एन.वी. अंजारिया और जस्टिस श्री विपुल एम. पंचोली की गरिमामयी उपस्थिति रही। इसके अलावा, गुजरात के उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी भी इस मौके पर मौजूद रहे। गुजरात के उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी भी इस मौके पर मौजूद रहे। गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (जीएसएलएसए) के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.वाई. कोगजे, गुजरात हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति और बिल्डिंग कमेटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति श्री ए.एस. सुपेहिया, राज्य के महाधिवक्ता श्री कमल त्रिवेदी सहित गुजरात हाई कोर्ट के अन्य न्यायमूर्ति उपस्थित रहे।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में प्रस्तावित वटवा मेगा कोचिंग टर्मिनल का निरीक्षण किया परियोजना से अहमदाबाद मंडल की परिचालन क्षमता में लगभग 3 गुना वृद्धि होगी

माननीय केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज अहमदाबाद में प्रस्तावित वटवा मेगा कोचिंग टर्मिनल परियोजना स्थल का दौरा कर कार्यों की प्रगति, एलाइनमेंट तथा प्रस्तावित आधुनिक सुविधाओं का निरीक्षण एवं विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक तथा अन्य वरिष्ठ रेलवे अधिकारी उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान परियोजना की मुख्य संरचना, परिचालन व्यवस्था तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित की जा रही सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अहमदाबाद तक प्रस्तावित चौहरीकरण (क्वाड्रपलिंग) कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की गई, जिससे भविष्य में यात्री ट्रेनों के संचालन में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित की जा सकेगी।

वटवा मेगा कोचिंग टर्मिनल भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना है, जिसका उद्देश्य अहमदाबाद जंक्शन पर बढ़ते परिचालन दबाव को कम करना तथा आधुनिक, सुरक्षित एवं कुशल रेल संचालन सुनिश्चित करना है।

परियोजना की प्रमुख विशेषताएँ:

▸▸ टर्मिनल की कुल प्रस्तावित लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है।

▸▸ टर्मिनल में 12 पिट लाइनें विकसित की जाएँगी, जिससे ट्रेनों का प्राथमिक मेंटेनेंस सुचारु रूप से किया जा सकेगा।

29 स्टेबलिंग लाइनें रेक की सुरक्षित पार्किंग हेतु उपलब्ध होंगी।

▸▸ रेक की सफाई के लिए 2 वॉशिंग लाइनें प्रस्तावित हैं।

▸▸ खराब कोचों की मरम्मत हेतु 600 मीटर लंबाई की 2 सिक लाइनें विकसित की जाएँगी।

▸▸ यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए 6 नए प्लेटफॉर्मों का निर्माण किया जाएगा, जिससे टर्मिनल पर कुल प्लेटफॉर्मों की संख्या 9 हो जाएगी।

माननीय मंत्री ने भविष्य की बढ़ती परिचालन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पिट लाइनों एवं स्टेबलिंग लाइनों की संख्या में और वृद्धि करने के निर्देश भी दिए।

▸▸ परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि

▸▸ परियोजना के पूर्ण संचालन के पश्चात: प्रतिदिन 36 जोड़ी ट्रेनों का प्राथमिक मेंटेनेंस संभव होगा।

▸▸ 15 ट्रेनों को प्लेटफॉर्म रिटर्न सुविधा उपलब्ध होगी।

▸▸ कुल मिलाकर 51 ट्रेनों का संचालन इस टर्मिनल से किया जा सकेगा।

इस परियोजना के माध्यम से अहमदाबाद मंडल की कुल परिचालन क्षमता में लगभग 3 गुना वृद्धि होने की संभावना है। वटवा मेगा कोचिंग टर्मिनल परियोजना भारतीय रेल के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, परिचालन दक्षता बढ़ाने तथा यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह परियोजना भविष्य की बढ़ती यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद सोला सिविल अस्पताल से निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण महाअभियान का राज्यव्यापी प्रारंभ कराया

▸▸ एचपीवी टीकाकरण के देशव्यापी शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति

▸▸ स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रफुलभाई पानसेरिया का राज्यव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान में भाग लेने का अनुरोध

▸▸ अनुमानित 5.50 लाख किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा देगा स्वदेशी टीका

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करकमलों से शनिवार को राजस्थान के अजमेर से राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ कराया गया, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री की वर्चुअल उपस्थिति में अहमदाबाद स्थित सोला सिविल अस्पताल में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रफुलभाई पानसेरिया की प्रेरक उपस्थिति में राज्यव्यापी एचपीवी टीकाकरण महाअभियान का भव्य प्रारंभ किया गया।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रफुलभाई पानसेरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात 2007 से पोलियोमुक्त बना है और अब टीकाकरण की प्रक्रिया अधिक सरल एवं प्रभावशाली बनी है। पूर्व में जिन रोगों के लिए विदेश से टीके मंगवाने पड़ते थे, आज भारत स्वदेशी टीके बनाकर विश्व की सहायता करने की क्षमता अर्जित कर चुका है, जो आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है।

श्री पानसेरिया ने आगे कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि सुदूरवर्ती-दूरदराजी व्यक्ति की भी दवाई या पैसे के अभाव में मृत्यु न हो। इसके लिए आयुष्मान कार्ड की उपचार खर्च सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई है। उन्होंने अंधश्रद्धा, अंधविश्वास तथा अफवाहों से दूर रहने का अनुरोध करते हुए कहा कि यह एचपीवी टीका वैज्ञानिक पद्धति से तथा चिकित्सकों की देखरेख में तैयार हुआ है। आज जब खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण कैंसर जैसे रोग बढ़ रहे हैं, तब उन्होंने पहला सुख निरोगी काया के सूत्र को सार्थक करने और हमारी बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए इस टीकाकरण अभियान में भाग लेने का अनुरोध किया।

गुजरात सरकार द्वारा व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम अंतर्गत हर वर्ष बच्चों के टीकाकरण पर 240 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाते हैं और अब इस कड़ी में एचपीवी टीके को भी शामिल किया गया है। बाजार में इस वैक्सीन के एक डोज की कीमत लगभग 3000 रुपए है, परंतु राज्य सरकार द्वारा 150 करोड़ रुपए आवंटित कर यह टीका पूरी तरह निःशुल्क लगाने का ऐतिहासिक निर्णय किया गया है।

इस महत्वाकांक्षी अभियान अंतर्गत गर्भाशय के मुख के कैंसर की रोकथाम के लिए राज्य की 14 वर्ष पूरे कर चुकी और 15 वर्ष से कम आयु की अनुमानित 5.50 लाख किशोरियों को टीकाकरण से सुरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में महिलाओं में होने वाले कुल कैंसर में सर्वाइकल कैंसर दूसरे स्थान पर है, जिसमें मुख्यतः एचपीवी-16 व एचपीवी-18 प्रकार के वायरस जिम्मेदार हैं। इस गंभीर स्थिति को ध्यान में रखकर अत्यंत प्रभावशाली तथा सुरक्षित क्वाड्रिवेलेंट एचपीवी वैक्सीन अब गुजरात की किशोरियों को प्रदान की जाएगी।

इस अभियान के सुचारु संचालन के लिए 2297 प्रशिक्षित टीकाकरण टीमें तथा इतने ही कोल्ड चेन पॉइंट्स कार्यरत किए गए हैं। टीके की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए +2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस तापमान में स्टोरेज की सुविधा के साथ TeCHO+ तथा SAFE-VAC पोर्टल पर रियल-टाइम ट्रैकिंग की जाएगी। सरकार द्वारा 'सर्वाइकल कैंसर से बेटी को बचाएँ, समय पर एचपीवी टीका लगवाएँ' के मंत्र के साथ सभी अभिभावकों से भावपूर्ण अपील की गई है कि वे अपनी 14 वर्ष की बेटियों को यह टीका लगवाकर उनके कैंसर मुक्त भविष्य की गारंटी सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभाबेन जैन, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री राजीव टोपनो, मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. रतनकँवर गढवीचारण, महानगर पालिका स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री देवांगभाई दाणी, मनपा में शासक पक्ष के नेता श्री गौरांगभाई प्रजापति, स्वास्थ्य विभाग व सोला सिविल अस्पताल के अधिकारी व कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में 14 वर्ष पूर्ण कर चुकीं बेटियाँ आदि उपस्थित रहे।

माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यों की समीक्षा

माननीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 28 फरवरी, 2026 को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का दौरा कर चल रहे पुनर्विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा कर कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

भारतीय रेल देशभर में 1300 से अधिक स्टेशनों के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण का कार्य कर रही है, जिनमें अहमदाबाद स्टेशन एक प्रमुख परियोजना है। परियोजना के अंतर्गत तीन नए प्लेटफॉर्म जोड़े जाएंगे, जिससे ट्रेनों के संचालन की क्षमता में वृद्धि होगी। स्टेशन को कालुपुर एवं सरसपुर दोनों ओर से आधुनिक स्वरूप प्रदान किया जा रहा है तथा इसे विश्वस्तरीय मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है।

समीक्षा के दौरान प्रस्तुत प्रगति विवरण के अनुसार, एमएमटीएच (Multi Modal Transport Hub) भवन के दक्षिण दिशा के निचले भाग का 58.2% कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि ऊपरी भाग का 24.0% कार्य प्रगति पर है। एमएमटीएच भवन की 7वीं एवं 8वीं मंजिल पर निर्माण कार्य वर्तमान में जारी है। पार्सल भवन टी–6 का 99.0% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। एलीवेटेड रोड परियोजना का 67.3% कार्य पूर्ण है तथा पियर संख्या P-1 से P-41 तक के सभी

निर्माण कार्य संपन्न हो चुके हैं। स्टेशन भवन (कॉनकोर्स एवं मेजेनाइन/रूफ संरचना) का 20.8% कार्य पूर्ण है तथा कॉनकोर्स संरचना की एरेक्शन प्रक्रिया प्रगति पर है।

परिसर को विश्वस्तरीय मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें पर्याप्त पार्किंग, एलीवेटेड सड़क तंत्र, सुसज्जित प्लाज़ा, विस्तृत कॉनकोर्स तथा आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी। विरासत संरचनाओं—'ईंट मीनार' एवं 'झूलता मीनार'—का संरक्षण भी परियोजना का अभिन्न हिस्सा है। लगभग 15 एकड़ में कॉनकोर्स प्लाज़ा तथा 7 एकड़ में मेजेनाइन प्लाज़ा विकसित किए जा रहे हैं, जहां आधुनिक प्रतीक्षालय, स्वच्छ शौचालय, फूड कोर्ट और वाणिज्यिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्टेशन को हरित भवन के रूप में विकसित करते हुए ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्नत निगरानी प्रणाली, स्वचालित पार्सल प्रबंधन तथा दिव्यांगजन-अनुकूल सुविधाएं भी परियोजना का प्रमुख हिस्सा हैं।

प्रमुख निर्माण गतिविधियों की वर्तमान स्थिति

▸▸ संरचनात्मक स्टील फैब्रिकेशन पाँचवीं मंजिल तक पूर्ण; छठी से आठवीं मंजिल तक लगभग 70% पूर्ण।

▸▸ संरचनात्मक एरेक्शन पाँचवीं मंजिल तक पूर्ण; छठी से आठवीं मंजिल का एरेक्शन कार्य प्रगति पर।

▸▸ डेक स्लैब कास्टिंग चौथी मंजिल तक पूर्ण; पाँचवीं मंजिल की स्लैब कास्टिंग लगभग 50% पूर्ण।

▸▸ पाँचवीं मंजिल पर कॉलम एन्केसिंग कार्य प्रगति पर।

▸▸ बेसमेंट एवं ग्राउंड फ्लोर में ब्लॉक वर्क एवं प्लास्टर लगभग 85% पूर्ण; प्रथम तल पर ब्लॉक वर्क प्रगति पर।

▸▸ प्लेटफॉर्म संख्या 10 एवं लाइन संख्या 16 पर प्लेटफॉर्म रिसर्फेसिंग, एमईपीएफ (Mechanical, Electrical, Plumbing & Fire Fighting) तथा बीएलटी (Ballastless Track) कार्य पूर्ण।

▸▸ प्लेटफॉर्म संख्या 9 एवं लाइन संख्या 15 पर बीएलटी (Ballastless Track) कार्य पूर्ण; प्लेटफॉर्म रिसर्फेसिंग कार्य प्रगति पर।

यह परियोजना पूर्ण होने पर आधुनिक रेलवे अवसंरचना एवं संरक्षित विरासत के संतुलित समावेशन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करेगी।

होली के अवसर पर पश्चिम रेलवे चलाएगी बांद्रा टर्मिनस – गोरखपुर के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन

यात्रियों की सुविधा तथा होली पर्व के दौरान बढ़ी हुई यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए, पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस – गोरखपुर के बीच विशेष किराये पर एक जोड़ी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रेन संख्या 09019 बांद्रा टर्मिनस – गोरखपुर विशेष दिनांक रविवार, 1 मार्च 2026 को बांद्रा टर्मिनस से 08:35 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 20:40 बजे गोरखपुर पहुँचेगी।

इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09020 गोरखपुर – बांद्रा टर्मिनस विशेष दिनांक सोमवार, 2 मार्च 2026 को गोरखपुर से 23:35 बजे प्रस्थान करेगी तथा बुधवार को 09:45 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी।

मार्ग में यह ट्रेन बोरिवली, पालघर, दहानु रोड, वापी, वलसाड, नवसारी, उधना, सायन, भरूच, वडोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम, नागदा, उज्जैन, मक्सी, शुजलपुर, सीहोर, संत हिरदाराम नगर, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, मनकापुर, बस्ती और खलीलाबाद स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहरेगी। इस ट्रेन में जनरल सेकंड क्लास के कोच होंगे। ट्रेन के समय एवं संरचना संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।

सप्ताह के दौरान सोने के वायदा में 4890 और चांदी के वायदा में 18276 की तेजी: क्रूड ऑयल के वायदा में 5 की नरमी

मुंबईः देश के प्रमुख कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर 20 से 26 फरवरी के सप्ताह के दौरान विभिन्न कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस तथा इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस में 4463716.26 करोड़ का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदा में 278820.75 करोड़ का कारोबार हुआ। कमोडिटी वायदा पर ऑप्शंस में 4184873.73 करोड़ का नॉशनल टर्नओवर दर्ज हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स मार्च वायदा 39489 पॉइंट के स्तर पर पहुंचा। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल साप्ताहिक प्रीमियम टर्नओवर 35105.58 करोड़ का रहा।

समीक्षा अधीन सप्ताह के दौरान कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदा में 216234.76 करोड़ का कारोबार हुआ। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सप्ताह की शुरुआत में 10 ग्राम प्रति 155105 के भाव पर खुला, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपरी स्तर 161729 और निचले स्तर 154890 पर पहुंचा, पिछले बंद 154819 के मुकाबले सप्ताह के अंत में 4890 की तेजी के साथ 159709 के भाव पर बंद हुआ। गोल्ड-गिन्नी मार्च वायदा 8 ग्राम प्रति 1917 की तेजी के साथ 130058 के भाव पर बंद हुआ। गोल्ड-पेटल मार्च वायदा 1 ग्राम प्रति 340 बढ़कर 16393 के भाव पर बंद हुआ। सोना-मिनी मार्च वायदा 10 ग्राम प्रति 4580 की बढ़ोतरी के साथ 157588 रहा। गोल्ड-टेन मार्च वायदा सप्ताह की शुरुआत में 10 ग्राम प्रति 157220 के भाव पर खुला, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपरी स्तर 162999 और निचले स्तर 157000 पर पहुंचा, पिछले बंद 156935 के मुकाबले सप्ताह के अंत में 3459 की तेजी के साथ 160394 रहा।

चांदी के वायदा में चांदी मार्च वायदा सप्ताह की शुरुआत में किलो प्रति 243874 के भाव पर खुला, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपरी स्तर 270500 और निचले स्तर 241245 पर पहुंचा, पिछले बंद 241393 के मुकाबले सप्ताह के अंत में 18276 की तेजी के साथ 259669 के स्तर पर पहुंचा। सप्ताह के अंत में किलो प्रति चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 20249 बढ़कर 271567 के स्तर पर पहुंचा। चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 20033 बढ़कर सप्ताह के अंत में 271590 रहा।

▸▸ कमोडिटी वायदा में 278820.75 करोड़ और कमोडिटी ऑप्शंस में 4184873.73 करोड़ का साप्ताहिक टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदा में 216234.76 करोड़ का साप्ताहिक कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स वायदा 39489 पॉइंट के स्तर पर

धातुओं में 35098.36 करोड़ का कारोबार हुआ। सप्ताह के अंत में किलो प्रति तांबा मार्च वायदा 20.25 बढ़कर 1207.3 के स्तर पर पहुंचा। जस्ता मार्च वायदा 2.7 बढ़कर 326.95 के भाव पर सप्ताह के अंत में बंद हुआ। एल्युमिनियम मार्च वायदा सप्ताह के अंत में 1.05 बढ़कर 312.1 के भाव पर बंद हुआ। सीसा मार्च वायदा 55 पैसे बढ़कर सप्ताह के अंत में 189.45 के भाव पर बंद हुआ।

एनर्जी सेगमेंट में 27408.46 करोड़ का कारोबार हुआ। एमसीएक्स इलेक्ट्रिसिटी मार्च वायदा सप्ताह की शुरुआत में MWh प्रति 3675 के भाव पर खुला, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपरी स्तर 4092 और निचले स्तर 3641 पर पहुंचा, सप्ताह के अंत में 316 बढ़कर 4004 के स्तर पर पहुंचा। क्रूड ऑयल मार्च वायदा सप्ताह की शुरुआत में बैरल प्रति 6078 के भाव पर खुला, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपरी स्तर 6134 और निचले स्तर 5801 पर पहुंचा, पिछले बंद 6058 के मुकाबले सप्ताह के अंत में 5 गिरकर 6053 के भाव पर बंद हुआ। क्रूड ऑयल-मिनी मार्च वायदा 7 गिरकर सप्ताह के अंत में 6053 रहा। नैचुरल गैस मार्च वायदा सप्ताह के अंत में MMBtu प्रति 14.3 गिरकर 257.1 रहा। नैचुरल गैस-मिनी मार्च वायदा 14.2 गिरकर सप्ताह के अंत में 257.2 के स्तर पर पहुंचा।

कृषि वस्तुओं के वायदा में मेंथा ऑयल मार्च वायदा सप्ताह की शुरुआत में किलो प्रति 968.5 के भाव पर खुला, सप्ताह के अंत में 14.1 गिरकर 956.2 रहा। इलायची मार्च वायदा सप्ताह की शुरुआत में किलो प्रति 2535 के भाव पर खुला, सप्ताह के अंत में 26 गिरकर 2524 रहा। कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर समीक्षा अधीन सप्ताह के दौरान सोने के विभिन्न वायदा में 117403.25 करोड़ और चांदी के विभिन्न वायदा में 98831.51 करोड़ का कारोबार हुआ। तांबे के वायदा में 29934.93 करोड़, एल्युमिनियम और एल्युमिनियम-मिनी के वायदा में 2339.93 करोड़, सीसा और सीसा-मिनी के वायदा में 249.02 करोड़, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदा में 2574.48 करोड़ का कारोबार हुआ। इलेक्ट्रिसिटी के वायदा में 168.27 करोड़ का कारोबार हुआ। क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदा में 10457.39 करोड़ का कारोबार हुआ। नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदा में 16782.80 करोड़ का कारोबार हुआ। इलायची के वायदा में 3.07 करोड़ का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सप्ताह के अंत में सोने के वायदा में 7764 लॉट, सोना-मिनी के वायदा में 32238 लॉट, गोल्ड-गिन्नी के वायदा में 15285 लॉट, गोल्ड-पेटल के वायदा में 201915 लॉट और गोल्ड-टेन के वायदा में 28958 लॉट के स्तर पर था। चांदी के वायदा में 3366 लॉट, चांदी-मिनी के वायदा में 13481 लॉट और चांदी-माइक्रो वायदा में 44513 लॉट के स्तर पर रहा। इलेक्ट्रिसिटी के वायदा में 1369 लॉट, क्रूड ऑयल के वायदा में 14972 लॉट, नैचुरल गैस के वायदा में 26470 लॉट के स्तर पर रहा। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो, बुलडेक्स मार्च वायदा 39901 पॉइंट के स्तर पर खुला, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपरी स्तर 40277 पॉइंट और निचले स्तर 39250 पॉइंट पर पहुंचा, सप्ताह के अंत में 528 पॉइंट बढ़कर 39489 पॉइंट के स्तर पर पहुंचा।